

रजिस्टर्ड नं 0 HP/13/SML/2001.



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 25 मार्च, 2002/4 चैत्र, 1924

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-171004, 25 मार्च, 2002

संख्या 1-22/2002-वि० स०.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2002

3585-राजपत्र/2002-25-3-2002—1,339.

(4547)

मूल्य : 1 रुपया।

(2002 का विधेयक संख्यांक-3) जो आज दिनांक 25 मार्च, 2002 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

अजय भण्डारी,
सचिव,

हिमाचल प्रदेश विधान सभा।

2002 का विधेयक संख्यांक 3

हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2002

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

पर्यटक व्यापार में लगे हुए व्यक्तियों के रजिस्ट्रीकरण और पर्यटन विकास बोर्ड का गठन तथा उससे सम्बद्ध मामलों या उससे सम्बन्धित विधि को पुनः अधिनियमित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्न-लिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय-1

प्रारम्भिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2002 है।

संक्षिप्त नाम,
विस्तार और
प्रारम्भ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. (1) राज्य सरकार यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के समस्त या उनमें से कोई उपबन्ध, ऐसी शर्तों और निबन्धनों के अध्वधीन, जैसी यह विनिर्दिष्ट करे, साधारणतया निम्नलिखित को लागू नहीं होंगे,—

छूट।

- (i) पूर्ण स्वरूप के लोक प्रयोजन के लिए प्रयुक्त परिसर या ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त परिसर के किसी वर्ग;
- (ii) लोक न्यास द्वारा धार्मिक या पूर्ण प्रयोजन के लिए, धारित और नाम-मात्र किराए पर दिए गए परिसर;
- (iii) लोक न्यास द्वारा धार्मिक या पूर्ण प्रयोजन के लिए, धारित और स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रशासित परिसर;
- (iv) सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रबन्ध किया गया या चलाया गया विश्राम-गृह, डाक बंगला, सकिट हाऊस, निरीक्षण कुटीर, सराय या किसी संस्था अथवा परिसर।

(2) राज्य सरकार, आदेश द्वारा यह निदेश भी दे सकेगी कि ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों के अध्वधीन, यदि कोई हों, अध्याय-4 के सभी या उनमें से कोई उपबन्ध, ऐसे होटलों या संस्थानों, या होटलों अथवा संस्थानों के ऐसे वर्ग को लागू नहीं होंगे, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

परिभाषाएं।

3. इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) “साहसिक खेल-कूद” से, भाग लेने वाले व्यक्ति के जीवन या अंग का जोखिम वाला, यथास्थिति, भूमि पर या जल में अथवा वायु में खेल-कूद या आमोद-प्रमोद हेतु बाह्य क्रियाकलाप, जिसमें जल-क्रीड़ा, वायु-क्रीड़ा, पैदल चलना (ट्रेकिंग), राफ्टिंग, स्कींग, हली-स्कींग और बंजी जम्पिंग, बैलूनिंग या सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित कोई अन्य खेल-कूद अभिप्रेत है ;
- (ख) “साहसिक खेल-कूद ऑपरेटर” से, व्यावसायिक आधार पर साहसिक खेल-कूद, अर्थात् प्रशिक्षण, आमोद-प्रमोद या क्रीड़ा के प्रयोजन के लिए लगा हुआ या लगने का प्रस्ताव करने वाला, यथास्थिति, कोई व्यक्ति या संगठन या उद्यम अभिप्रेत है ;
- (ग) “बोर्ड” से, इस अधिनियम की धारा 4 के अधीन स्थापित पर्यटन विकास बोर्ड अभिप्रेत है ;
- (घ) “रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र” से, इस अधिनियम के अधीन जारी किया गया प्रमाण-पत्र अभिप्रेत है ;
- (ङ) “परिषद्” से, इस अधिनियम की धारा 17 के अधीन स्थापित पर्यटन विकास परिषद् अभिप्रेत है ;
- (च) “सरकार” से, हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है ;
- (छ) “गाइड” से, ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो पर्यटकों के लिए स्वयं वैतनिक गाइड के रूप में लगा हुआ है ;
- (ज) “स्थानीय प्राधिकरण” से, नगर निगम या नगरपालिका परिषद् या छावनी बोर्ड या नगर पंचायत या ग्राम पंचायत या विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है ;
- (झ) “अनाचार” के अन्तर्गत है छल, दलाली, प्रतिरूपण, ठहरने या यात्रा के प्रबन्ध में स्वतन्त्र चयन में बाधा डालना, इस अधिनियम के अधीन नियत से अधिक किराया या पारिश्रमिक प्रभारित करना, किराए की सूची प्रदर्शित करने में असफल रहना, केशमैमों देने में असफल रहना, अनुबन्ध अवधि के भीतर तथा सहमत हुए निबन्धनों के अनुसार आदेश के निष्पादन में जानबूझ कर असफल रहना, और साहसिक खेल-कूद ऑपरेटर द्वारा उपलब्ध होने पर पर्यटकों को वास-सुविधा की व्यवस्था करने में असफल रहना, वचन की गई सुविधाएं देने में असफल रहना, और घटिया उपस्कर और अप्रशिक्षित कार्मिकों की व्यवस्था करना ;

स्पष्टीकरण.—“दलाली” पद से, वास-सुविधा, परिवहन, सैर-सपाटे के लिए अवपीडित करना या किसी विशेष परिसर, स्थापन या व्यक्तिगत लाभ के प्रतिफल से पर्यटन सम्बन्धी किसी अन्य सेवा के लिए परेशान करना अभिप्रेत है ;

- (ज) "राजपत्र" से, राजपत्र, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है;
- (ट) "विहित" से, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
- (ठ) "विहित प्राधिकारी" से, सरकार द्वारा इस रूप में अधिसूचित प्राधिकारी अभिप्रेत है; परन्तु विभिन्न क्षेत्रों के लिए तथा इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के लिए विभिन्न प्राधिकारी अधिसूचित किए जा सकेंगे;
- (ड) "सीजन" से, 15 अप्रैल से 15 जुलाई और 15 सितम्बर से 15 जनवरी तक की अवधि अभिप्रेत है; और शेष अवधि "ऑफ सीजन" होगी;
- (ढ) "पर्यटन इकाई" से, सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित पर्यटकों को सुविधाएं और सेवाएं उपबन्धित करने वाला कोई स्थापन अभिप्रेत है और जिसमें होटल रिजार्ट, मोटल, समय शेयर इकाईयां, खण्ड (अपार्टमेंट), गृह नौकाएं, मोटर कारवां, अतिथि गृहों, यात्री निवासों, रेस्तरां और गरब घर, आमोद-प्रमोद पार्क, थीम पार्क, जल-क्रीड़ा केन्द्र, वायु-क्रीड़ा केन्द्र, गॉल्फ के मैदान, हस्तशिल्प ग्राम प्रक्षेत्र, शिविर, सरिता परिभ्रमण (रिवर क्रूज), झील परिभ्रमण योजना, प्रकाश और ध्वनि प्रदर्शन, साहसिक खेल-कूद प्रक्षेत्र, धनीय प्रतिफल हेतु साहसिक खेल-कूद के लिए प्रशिक्षण संस्थान/पर्यटन उद्योग के लिए कारबार करने वाले और सरकार द्वारा समय-समय पर, जैसा अधिसूचित किया जाए, किसी अन्य प्रकार का स्थापन भी है।
- (ण) "पर्यटन इकाई ऑपरेटर" से, ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो पर्यटन इकाई का स्वामी हो, इसे चलाता हो या परिचालन करता हो, और इसके अन्तर्गत स्वत्वधारी की ओर से कामकाज का प्रबन्ध करने या परिचालन करने वाला व्यक्ति भी है;
- (त) "पर्यटक" से, हिमाचल प्रदेश राज्य में यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों सहित, कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अभिप्रेत है;
- (थ) "यात्रा अभिकर्ता" से, धनीय प्रतिफल हेतु पर्यटकों के लिए यात्रा इंतजाम के कारबार में लगा हुआ व्यक्ति अभिप्रेत है;

स्पष्टीकरण.—"यात्रा इंतजाम" शब्द प्रयोग के अन्तर्गत निम्नलिखित है:—

- (क) किसी भी ढंग द्वारा, परिवहन के लिए इंतजाम;
- (ख) खान-पान सहित या रहित आवास के लिए इंतजाम; और
- (ग) अन्य सेवाएं करना, जैसे कि क्रीड़ा और खेल-कूद या पर्यटक के व्यक्तिगत सामान की प्राप्ति या निगम अथवा पर्यटक के फोटोचित्र लेने के लिए इंतजाम करना, गाइडों, फोटोग्राफरों को भाड़े पर लेना, यात्रा या साहसिक खेल-कूद के लिए उपस्करों का इंतजाम करना।

अध्याय-2

पर्यटन विकास बोर्ड

बोर्ड की 4. (1) सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, स्थापना और राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा "पर्यटन विकास बोर्ड" के नाम से जाना जाने वाला बोर्ड, गठन। स्थापित कर सकेगी।

(2) बोर्ड, उपर्युक्त नाम से एक निगमित निकाय होगा, उसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी, जिसे सम्पत्ति अर्जित करने, रखने तथा व्ययन करने सहित, संविदा करने की शक्ति होगी तथा उसके नाम से वाद ला सकेगा या उसके विरुद्ध वाद लाया जा सकेगा।

(3) बोर्ड, निम्नलिखित सदस्यों से गठित होगा :—

(i) सरकारी सदस्य :

(क) मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश	अध्यक्ष।
(ख) पर्यटन मन्त्री, हिमाचल प्रदेश	उपाध्यक्ष।
(ग) मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार	सदस्य।
(घ) सचिव (पर्यटन), हिमाचल प्रदेश सरकार	सदस्य।
(ङ) सचिव (वित्त), हिमाचल प्रदेश सरकार	सदस्य।
(च) सचिव (वन), हिमाचल प्रदेश सरकार	सदस्य।
(छ) सचिव (लोक निर्माण विभाग), हिमाचल प्रदेश सरकार	सदस्य।
(ज) सचिव (शहरी विकास), हिमाचल प्रदेश सरकार	सदस्य।
(झ) सचिव (नगर और ग्राम योजना), हिमाचल प्रदेश सरकार	सदस्य।
(ञ) सचिव (युवा सेवाएं एवं खेल-कूद), हिमाचल प्रदेश सरकार।	सदस्य।
(ट) सचिव (स्वास्थ्य/आयुर्वेद), हिमाचल प्रदेश सरकार	सदस्य।
(ठ) सचिव (उद्यान), हिमाचल प्रदेश सरकार	सदस्य।
(ड) सचिव (आबकारी), हिमाचल प्रदेश सरकार	सदस्य।
(ढ) सचिव (उद्योग), हिमाचल प्रदेश सरकार	सदस्य।
(ण) सचिव (योजना), हिमाचल प्रदेश सरकार	सदस्य।
(त) सचिव (विधि), हिमाचल प्रदेश सरकार	सदस्य।
(थ) सचिव (भाषा, कला एवं संस्कृति), हिमाचल प्रदेश सरकार	सदस्य।

(ii) गैर-सरकारी सदस्य :

(क) होटल संगम के प्रतिनिधि	चार सदस्य।
(ख) यात्रा अभिकर्ता संगम के प्रतिनिधि	दो सदस्य।
(ग) साहसिक खेल-कूद ऑपरेटर संगम के प्रतिनिधि	दो सदस्य।
(घ) पर्यटन उद्योग के अन्य हित वाले समूहों के प्रतिनिधि	दो सदस्य।
(ङ) सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा, उन व्यक्तियों में से जिन्होंने पर्यटन उद्योग के विकास और प्रोन्नति के क्षेत्र में उत्कृष्ट अंशदान किया है, या निपुणता है, और जिनको पर्यटन व्यवसाय में कम से कम दस वर्षों के कार्यकरण	

का अनुभव है, नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले तीन गैर-सरकारी सदस्य ।

(च) रजिस्ट्रीकृत गैर-सरकारी संगठन के प्रतिनिधि दो सदस्य ।

(iii) निदेशक (पर्यटन), हिमाचल प्रदेश सदस्य-सचिव
पदेन सदस्य ।

(4) गैर-सरकारी सदस्यों को, ऐसे भत्ते संदत्त किए जाएंगे, जैसे विहित किए जाएं ।

5. (1) गैर-सरकारी सदस्यों की पदावधि, दो वर्ष होगी और वे पुनःनियुक्ति पदावधि के पात्र होंगे ।

(2) यदि सरकार मानती है कि किसी गैर-सरकारी सदस्य का कार्यालय में बना रहना बोर्ड के हित में नहीं है, तो सरकार उसकी अवधि को समाप्त करने का आदेश कर सकेगी, और तदुपरि इस तथ्य के होते हुए भी कि उस अवधि जिसके लिए वह नियुक्त किया गया था, समाप्त नहीं हुई है, वह बोर्ड का सदस्य नहीं रहेगा ।

(3) बोर्ड का कोई भी गैर-सरकारी सदस्य, अध्यक्ष के नाम पत्र द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा । त्यागपत्र, अध्यक्ष द्वारा उसके त्यागपत्र की स्वीकृति की तारीख से प्रभावी होगा ।

6. कोई व्यक्ति, गैर-सरकारी सदस्य के रूप में निर्वाहित होगा, यदि,— निरहंता ।

(क) वह ऐसे अपराध जिसमें सरकार की राय में नैतिक अधमता है, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है और कारावास से दण्डादिष्ट किया गया है और ; या

(ख) वह अनुमोचित दिवालिया है ; या

(ग) वह विकृतचित्त का है ; या

(घ) वह सरकार या सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी निगम की सेवा से पदच्युत कर दिया है या हटा दिया गया है ; या

(ङ) उसका बोर्ड के साथ, के द्वारा या की ओर से, स्वयं या किसी भागीदार, नियोजक या कर्मचारी द्वारा किसी संविदा या नियोजन में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः भ्रंश या हित है ।

7. (1) बोर्ड, निम्नलिखित शर्तों के अधीन इसकी बैठकों के दिन, समय, नोटिस, प्रबन्ध और स्थगन के बारे में, समय-समय पर, जैसा वह उचित समझे, ऐसे प्रबन्ध और बैठक करेगा,— बोर्ड की बैठकें ।

(क) साधारण बैठक वर्ष में दो बार होगी ;

(ख) अध्यक्ष, जब कभी ठीक समझता हो, विशेष बैठक बुला सकेगा ;

(ग) प्रत्येक बैठक, अध्यक्ष द्वारा और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा और दोनों की अनुपस्थिति में, उपस्थित सदस्यों द्वारा चुने गए किसी अन्य सदस्य द्वारा संचालित की जाएगी ;

(घ) बोर्ड का सदस्य-सचिव, बैठक के होने से कम से कम चौबीस घण्टे पूर्व, बोर्ड के सभी सदस्यों को बैठक की कार्यसूची सहित, नोटिस उपलब्ध करवाएगा ; और

(ङ) बोर्ड के सदस्यों की कुल संख्या का पचास प्रतिशत बैठक की गणपूर्ति करेगा ।

(2) बोर्ड के विनिश्चय, बोर्ड के सदस्य-सचिव द्वारा अनुप्रमाणित और अनुरक्षित किए जाएंगे ।

बोर्ड की
शक्तियां
और कृत्य ।

8. (1) बोर्ड,—

- (क) सरकार को, राज्य में पर्यटन उद्योग के विकास और प्रोन्नति हेतु नीति मार्गदर्शन अधिकथित करने का परामर्श दे सकेगा ;
- (ख) हिमाचल को देश के भीतर और बाहर आकर्षक पर्यटक गन्तव्य स्थान के रूप में, प्रचारित कर सकेगा और सुरक्षित विश्वसनीय पर्यटक गन्तव्य स्थान के रूप में हिमाचल प्रदेश की प्रतिभा स्थापित कर सकेगा ;
- (ग) बोर्ड के साधनों के भीतर सम्भव विस्तार तक, पर्यटक क्षेत्रों में अभिवृद्धि का वचन दे सकेगा ;
- (घ) पर्यटन उद्योग/पर्यटकों के फायदे के लिए सामान्यतः आय उत्पन्न करने की परियोजनाओं का वचन दे सकेगा ;
- (ङ) पर्यटक उद्योग को प्रोन्नत करने और ऐसे विभागों तथा अभिकरणों के साथ संयुक्त उद्यम में प्रवेश करने हेतु पर्यटन विभाग, पर्यटन विकास परिषद्, पर्यटन विकास निगम, सरकारी, अर्द्ध-सरकारी संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों के अन्य विभागों को सहायता प्रदान कर सकेगा ;
- (च) राज्य में, रक्षणीय पर्यटन उद्योग के विकास के लिए मानव संसाधन विकास के प्रयत्न का वचन दे सकेगा ;
- (छ) पर्यटन उद्योग के सम्पूर्ण विकास के लिए अन्य राज्यों के प्रतिस्थानी निकायों के सहयोग में कार्य कर सकेगा और देश में तथा अन्यत्र अन्य सरकारी और अर्द्ध-सरकारी संगठनों के साथ संयुक्त परियोजनाओं का वचन दे सकेगा ;
- (ज) पर्यटन और सिविल विमानन के विकास, विस्तार एवं प्रोन्नति के माध्यम से, रोजगार अवसर उत्पन्न कर सकेगा और विदेशी मुद्रा उपार्जित कर सकेगा ;
- (झ) पर्यटन के सैक्टर में आई समस्याओं को दूर करने के तरीके ढूँढने का कार्य अनुसंधान कार्यान्वित कर सकेगा या आवश्यकता के अनुसार कार्यान्वित करवा सकेगा ताकि पर्यटकों को उत्कर्ष सेवाएं उपलब्ध की जा सकें ;
- (ञ) संगठित और प्रभावी रीति में पर्यटन से सम्बन्धित विद्यमान भौतिक अव-संरचना का प्रयोग करके, पर्यटकों को राज्य के धार्मिक और सांस्कृतिक

महत्व के स्थानों, ऊँचे पर्वतों और प्राकृतिक सौंदर्य के लुभावने क्षेत्रों की यात्रा करने को प्रोत्साहित करने हेतु, निजी क्षेत्र को प्रेरित करने के लिए कदम उठा सकेगा ;

- (ट) अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी और सम्मेलनों, व्यापार मेले, युवा सांस्कृतिक त्यौहारों और खेल प्रतियोगिताओं सहित, आन्वयिक और पर्यटन प्रोन्नति क्रियाकलापों का आयोजन करने और ऐसे क्रियाकलापों का आयोजन करने और शामिल होने के लिए, निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के कदम उठा सकेगा ;
- (ठ) जब नए पर्यटक गन्तव्यों को विकसित करना हों, और पर्यटन अवसंरचना तथा सुविधाओं का समेकन करना हो, और ग्रामीण पर्यटन विकास के लिए विभिन्न क्रियाकलापों का जिम्मा लेने हेतु स्थानीय ग्रामीण समुदाय को प्रेरित करना हो, तब ग्रामीण पर्यटन गन्तव्यों को प्राथमिकता दे सकेगा ;
- (ड) नए पर्यटक गन्तव्यों की भवन निर्माण अवसंरचना और विकास के लिए, विनिधान संचारित कर या करवा सकेगा ;
- (ढ) अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने तथा धार्मिक पर्यटन का विकास करने और धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व के ऐसे स्थानों में सुविधाओं और सेवाओं का विस्तार करने हेतु, पर्यटकों की अभिरुचि वाले धार्मिक स्थानों को संरक्षित और प्रोन्नत कर सकेगा ;
- (ण) वन्य प्राणी और 'ईको टूरिज्म' को विकसित और प्रोन्नत कर सकेगा ;
- (त) पर्यटन चेतना बढ़ाने हेतु विभिन्न स्तरों पर प्रचार कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर या करवा सकेगा ;
- (थ) पर्यटन उद्यमकर्ताओं द्वारा, पर्यटकों को उपबंधित सेवाओं और सुविधाओं के मानवीकरण द्वारा पर्यटकों की सुरक्षा हेतु विशेष प्रबन्ध कर सकेगा ;
- (द) पर्यटन से सम्बन्धित विषयों में आवश्यक सेवाओं और परामर्श के लिए उपबन्ध कर सकेगा और उपबन्ध करवा सकेगा ;
- (ध) बोर्ड के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, सरकार के अनुमोदन से, विदेशी या अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से बातचीत कर सकेगा ;
- (न) बोर्ड के वार्षिक कार्यक्रमों के संचालन के लिए आवश्यक बजट का अनुमोदन कर सकेगा ;
- (प) पर्यटन के विकास, विस्तार और प्रोन्नति से सम्बन्धित अन्य आवश्यक क्रियाकलापों का पालन कर सकेगा ;
- (फ) पर्यटन विकास परिषदों को मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी कर सकेगा ;
- (ब) साहसिक पर्यटन से सम्बन्धित सोसाइटी के निर्माण और कृत्य करने में सहायता कर सकेगा ; और

(भ) ऐसे अन्य कृत्यों, जैसे सरकार द्वारा इसे समय-समय पर न्यस्त किए जाएं, का पालन कर सकेगा ।

(2) बोर्ड, सरकार के अनुमोदन से, निम्नलिखित के लिए फीस या किराया ले सकेगा,—

(क) पर्यटन इकाईयों, यात्रा अभिकर्ताओं, गाइडों, साहसिक खेलकूद ऑपरेटरों या इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण/अनुज्ञप्ति की अपेक्षा करने वाले अन्य व्यक्तियों के रजिस्ट्रीकरण और नवीकरण के रजिस्ट्रीकरण ; और

(ख) सामान्य प्रचार के रूप में गन्तव्य/अवस्थिति की प्रोन्नति ।

(3) बोर्ड, स्वप्रेरणा से निम्नलिखित के लिए फीस या किराया ले सकेगा,—

(क) बोर्ड द्वारा पर्यटकों को यानों के लिए, उपबन्धित की गई पार्किंग ;

(ख) बोर्ड द्वारा पर्यटन इकाईयों में पर्यटकों को उपबन्धित सुविधाओं के लिए ।

(4) बोर्ड, किसी सरकारी, अर्द्ध-सरकारी या गैर-सरकारी संगठनों से दान और अनुदान प्राप्त कर सकेगा ।

सरकार द्वारा बोर्ड को अनुदान । 9. सरकार, विधान मण्डल द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात्, बोर्ड को ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जो सरकार अवधारित करे, उधारों या अनुदानों के रूप में इतनी धनराशियों का संदाय कर सकेगी, जितनी सरकार, बोर्ड द्वारा इस अधिनियम के अधीन बोर्ड के कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए आवश्यक समझे ।

बोर्ड की निधियां । 10. (1) बोर्ड की अपनी निधि होगी और बोर्ड की सभी प्राप्तियां, उसमें जमा की जाएंगी तथा बोर्ड के सभी संदाय उसमें से किए जाएंगे ।

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यक्षों, बोर्ड को, बोर्ड के सभी प्रशासनिक व्ययों और उद्देश्यों पर या इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत प्रयोजनों के लिए, ऐसी राशि जो वह उचित समझे, खर्च करने की शक्ति होगी और ऐसी राशि बोर्ड की निधियों में से व्यय के रूप में मानी जाएगी ।

(3) बोर्ड के खाते में जमा समस्त धन, जिसे उप-धारा (2) में उपबन्धित के अनुसार तुरन्त उपयोजित न किया जा सकता हो, को भारतीय स्टेट बैंक या ऐसे अनुसूचित बैंक या राज्य सहकारिता बैंक अथवा डाकखाना में ऐसी शर्तों के अध्यक्षों, जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर विहित की जाएं, निक्षिप्त किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण.—इस उप-धारा में “अनुसूचित बैंक” पद का वही अर्थ है जैसा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 2 के खण्ड (ड) में इसे निर्दिष्ट किया गया है । 1934 का

निधियों का विनिधान । 11. बोर्ड अपनी निधियों का, सरकार की प्रतिभूतियों में या ऐसी अन्य रीति में, जैसी विहित की जाए, निवेश कर सकेगा ।

12. (1) बोर्ड, सरकार के अनुमोदन से या सरकार द्वारा इसे प्रदत्त किसी सामान्य या विशेष प्राधिकार के निबन्धनों के अनुसार, इस अधिनियम के अधीन, इस के सभी या किन्हीं कृत्यों का निर्वहन करने के लिए, बन्धपत्र, डिबेन्चर या ऐसे अन्य उपकरण, जैसा वह ठीक समझे, जारी करके किसी स्रोत से धन उधार ले सकेगा। बोर्ड की उधार लेने की शक्ति।

(2) सरकार, उप-धारा (1) के अधीन बोर्ड द्वारा उधार लिए गए ऋण की बाबत, मूल के प्रति संदाय और तदुपरि ब्याज के संदाय को, ऐसी रीति में जैसी वह ठीक समझे, प्रत्याभूति दे सकेगी।

(3) बोर्ड, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए, ऐसी परिसीमाओं के अध्यक्षीन, जैसी सरकार समय-समय पर अधिकृत करे, ओवरड्राफ्ट के स्वरूप द्वारा या अन्यथा, ऐसी राशि जैसी वह अपेक्षा करे, अस्थायी रूप से उधार ले सकेगा।

13. (1) सरकार, पर्यटन विभाग या किसी अन्य विभाग से, अपने ऐसे कर्म-चारियों, जैसे वह आवश्यक समझे, को बोर्ड की सेवा में प्रतिनियुक्त कर सकेगी। बोर्ड के कर्मचारी।

(2) प्रतिनियुक्त कर्मचारियों की सेवा की शर्तें ऐसी होंगी, जैसी राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विहित की जाएं।

(3) बोर्ड, संविदा के आधार पर किसी व्यक्ति को, जैसा वह आवश्यक समझे, ऐसी शर्तों और निबन्धनों पर जैसी इसके (बोर्ड) द्वारा अवधारित की जाएं, नियोजित कर सकेगा।

14. (1) बोर्ड, उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख बनाए रखेगा तथा लाभ और हानि लेखा तथा तुलनपत्र सहित लेखों का एक वार्षिक विवरण ऐसे प्ररूप में तैयार करेगा, जैसा सरकार द्वारा विहित किया जाए। लेखे और संपरीक्षा।

(2) बोर्ड के लेखे, हिमाचल प्रदेश के स्थानीय संपरीक्षा विभाग द्वारा प्रति वर्ष संपरीक्षित किए जाएंगे और ऐसी संपरीक्षा के बारे में उसके द्वारा उपगत कोई व्यय, बोर्ड द्वारा हिमाचल प्रदेश के स्थानीय संपरीक्षा विभाग को संदेय होगा।

(3) हिमाचल प्रदेश के स्थानीय संपरीक्षा विभाग के ऐसी संपरीक्षा के सम्बन्ध में वही अधिकार तथा विशेषाधिकार और प्राधिकार होंगे, जैसे महालेखाकार, हिमाचल प्रदेश के सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के सम्बन्ध में हैं और विशिष्टतया बोर्ड की पुस्तकों, बहियों, लेखों से सम्बन्धित वाऊचरों, दस्तावेजों और कागज पत्रों को पेश किए जाने की मांग करने का अधिकार होगा।

(4) हिमाचल प्रदेश के स्थानीय संपरीक्षा विभाग द्वारा यथाप्रमाणित बोर्ड के लेखे, उसकी संपरीक्षा रिपोर्ट सहित, सरकार को प्रत्येक वर्ष भेजे जाएंगे और सरकार उन्हें विधान सभा के समक्ष रखवाएगी।

15. (1) धारा 14 में किसी बात के होते हुए भी, सरकार किसी विशिष्ट अवधि के लिए विशिष्ट संव्यवहार या संव्यवहार के वर्ग या आवली से सम्बन्धित बोर्ड के लेखों की, ऐसे व्यक्ति या अभिकरण द्वारा, जैसा वह उचित समझे, विशेष संपरीक्षा संचालित किए जाने का आदेश दे सकेगी। लेखों की विशेष संपरीक्षा।

(2) जहां, उप-धारा (1) के अधीन आदेश किया जाता है, बोर्ड, संपरीक्षा के लिए ऐसे लेखे प्रस्तुत करेगा या करवाएगा और उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त किए गए व्यक्ति या अभिकरण को ऐसी सूचना देगा जैसी उक्त व्यक्ति या अभिकरण संपरीक्षा के प्रयोजन हेतु अपेक्षा करे।

वार्षिक
रिपोर्ट।

16. बोर्ड का सदस्य-सचिव, वित्तीय वर्ष के अवसान की तारीख से तीन मास के भीतर, बोर्ड के क्रियाकलापों की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसकी एक प्रति, सरकार को अग्रेषित करेगा।

अध्याय-3

पर्यटन विकास परिषद्

परिषद् की
स्थापना और
गठन।

17. (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, विनिर्दिष्ट पर्यटक स्थल, जैसा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, "पर्यटन विकास परिषद्" के नाम से जानी जाने वाली परिषद् की स्थापना कर सकेगी।

(2) परिषद्, उपर्युक्त नाम की एक निगमित निकाय होगी, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी, जिसे सम्पत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने और संविदा करने की शक्ति होगी और उक्त नाम से वह वाद ला सकेगी या उस पर वाद लाया जा सकेगा।

(3) परिषद्, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी :—

(i) सरकारी सदस्य :

(क) उपायुक्त	अध्यक्ष।
(ख) अतिरिक्त उपायुक्त या उसकी अनुपस्थिति में सम्बद्ध उप-मण्डल अधिकारी (सिविल)	उपाध्यक्ष।
(ग) वन मण्डल अधिकारी	सदस्य।
(घ) अधिशासी अभियन्ता (लोक निर्माण विभाग)	सदस्य।
(ङ) अधिशासी अभियन्ता (सिवाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग)	सदस्य।
(च) यथास्थिति, नगरपालिक परिषद्/नगर पंचायत/ग्राम पंचायत का कार्यपालक अधिकारी या सचिव	सदस्य।
(छ) नगर योजनाकार	सदस्य।

(ii) गैर-सरकारी सदस्य :

(क) होटल संगमों के प्रतिनिधि	दो सदस्य।
(ख) यात्रा अभिकर्ता संगमों के प्रतिनिधि	एक सदस्य।
(ग) पर्यटन उद्योग के अन्य हितबद्ध समूह से प्रतिनिधि	दो सदस्य।

(घ) सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा, उन व्यक्तियों में से जिन्हें पर्यटन उद्योग के विकास और प्रगति के क्षेत्र में और पर्यटन तथा यात्रा व्यवसाय के कार्यकरण में, कम से कम 10 वर्ष का अनुभव है, और परादेय योगदान/मुविज्ञता है, नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले चार गैर-सरकारी सदस्य।

(iii) सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाने वाला जिला पर्यटन विकास अधिकारी या सहायक पर्यटन विकास अधिकारी।

पदेन सदस्य-
मंचिव।

(4) गैर-सरकारी सदस्यों को ऐसे भत्ते संदत्त किए जाएंगे, जैसे राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए जाएं।

18. (1) गैर-सरकारी सदस्य, उनकी नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए परिषद् का पद धारण करेंगे और वह पुनः नियुक्त होने के पात्र होंगे।

पदावधि।

(2) यदि सरकार मानती है कि किसी गैर-सरकारी सदस्य का कार्यालय में बने रहना परिषद् के हित में नहीं है, तो सरकार, उसकी अवधि समाप्त करने का आदेश पारित कर सकेगी और तदुपरि, इस बात के होते हुए कि वह अवधि, जिसके लिए वह नामनिर्दिष्ट किया गया था, समाप्त नहीं हुई है, परिषद् का सदस्य नहीं रहेगा।

(3) परिषद् का कोई गैर-सरकारी सदस्य, अध्यक्ष के नाम पत्र द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा और त्यागपत्र, अध्यक्ष द्वारा उसके त्यागपत्र की स्वीकृति की तारीख से प्रभावी होगा।

19. व्यक्ति गैर-सरकारी सदस्य के रूप में निरहित होगा यदि,—

निरहता।

(क) वह ऐसे किसी अपराध जिसमें सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्गस्त है, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है और कारावास से दण्डादिष्ट किया गया है; या

(ख) वह अनुमोचित दिवालिया है; या

(ग) वह विकृतचित्त का है; या

(घ) वह सरकार या सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी निगम की सेवा से पदच्युत कर दिया या हटा दिया गया है; या

(ङ) उसका स्वयं या किसी भागी, नियोजक या कर्मचारी द्वारा, परिषद् के द्वारा या की ओर से किसी संविदा या नियोजन में प्रत्यक्षतः कोई अंश या हित है।

20. (1) परिषद् की साधारण बैठक, त्रिमास में एक बार, अध्यक्ष द्वारा नियत तारीख, समय और स्थान पर होगी।

परिषद् की बैठकें।

(2) अध्यक्ष, जब कभी उचित समझता हो, विशेष बैठक बुला सकेगा।

(3) परिषद् की प्रत्येक बैठक, अध्यक्ष और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष और दोनों की अनुपस्थिति में, उपस्थित सदस्यों द्वारा चुने गए किसी अन्य सदस्य की अध्यक्षता में की जाएगी।

(4) परिषद् का सदस्य-सचिव, बैठक के कम से कम चौबीस घण्टे पूर्व, परिषद् के सभी सदस्यों को बैठक की कार्यसूची के साथ नोटिस उपलब्ध करवाएगा।

(5) परिषद् के कुल सदस्यों के पचास प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति, बैठक की गणपूर्ति होगी।

(6) परिषद् की बैठक की कार्यवाहियां, अध्यक्ष द्वारा अनुप्रमाणित की जाएंगी और परिषद् के सदस्य-सचिव द्वारा बनाए रखी जाएंगी।

(7) परिषद्, इसके कृत्यों और क्रियाकलापों का, पालन करने के लिए जैसा आवश्यक समझे, उप-समितियां बना सकेगी।

(8) उप-धारा (7) के अधीन बनाई गई उप-समितियों के कर्तव्य, कृत्य और पदावधि परिषद् द्वारा अवधारित किए जाएंगे।

परिषद् की
शक्तियां
और कृत्य।

21. (1) परिषद्, इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, बोर्ड के आवश्यक कार्यक्रमों और सभी क्रिया-कलापों के प्रबन्ध को सुव्यवस्थित रूप से निष्पादित करेगी और निष्पादित करवाएगी।

(2) परिषद्,—

(क) पर्यटन से सम्बन्धित सेवाएं जैसे कि सूचना, आरक्षण, मार्गदर्शन, पाकिंग, प्रसाधन, पर्यटक स्थलों की सफाई, पर्यावरण उन्नत करने, प्रचार इत्यादि, की व्यवस्था और अनुरक्षण कर सकेगी;

(ख) पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता और अवसंरचनात्मक सुविधाएं बनाए रखने में स्थानीय निकायों की सहायता कर सकेगी;

(ग) उपवन, झील और आमोद-प्रमोद केन्द्र, फव्वारा या कोई अन्य ऐसी सुविधा बनवा और उसका अनुरक्षण कर सकेगी, जो क्षेत्र के पर्यटन मूल्य की वृद्धि करें;

(घ) पर्यटन उद्योग के विभिन्न विभागों और जो सम्बद्ध क्रियाकलापों में लगे हुए हैं, के लिए विकासात्मक उपाय कर सकेगी;

(ङ) बोर्ड के साधारण अधीक्षण और नियन्त्रण के अधधीन, सभी पर्यटन इकाईयों और सम्बद्ध क्रियाकलापों के सन्निर्माण, विस्तार, अनुरक्षण और संचालन को ऐसी रीति में, जिससे पर्यटन क्रियाकलाप पर्यावरणिक रूप से तथा सांस्कृतिक रूप से संपोषित बन जाएं, विनियमित कर सकेगी;

(च) अपने क्षेत्र के लिए पर्यटन महायोजना (मास्टर प्लान) तैयार कर सकेगी और पर्यटन सम्बन्धी क्रियाकलापों का अनुपालन करने वाली सभी पर्यटन इकाइयाँ और स्थापन, उपर्युक्त महायोजना (मास्टर प्लान) की पुष्टि करेंगे तथा परिषद् महायोजना की पुष्टि न करने वाली इकाइयों या स्थापनों को बन्द करने का आदेश कर सकेगी ;

(छ) ऐसे अन्य कर्तव्यों और कृत्यों, जैसे बोर्ड या सरकार द्वारा समय-समय पर इसे न्यस्त किए जाएँ, का अनुपालन कर सकेगी ।

(3) परिषद्,—

(i) इसके द्वारा उपबन्धित की गई किन्हीं प्रत्यक्ष सेवाओं पर फीस प्रभावित कर सकेगी ; और

(ii) बोर्ड, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, अर्द्ध-सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों तथा किसी अन्य स्त्रोत से दान या अनुदान प्राप्त कर सकेगी ।

22. (1) परिषद्, उचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख बनाए रखेगी तथा लाभ और हानि लेखा और तुलनपत्र सहित, लेखे का वार्षिक विवरण ऐसे प्ररूप में, जैसा सरकार द्वारा विहित किया जाए, तैयार करेगी ।

लेखे और संपरीक्षा ।

(2) परिषद् के लेखों की वार्षिक संपरीक्षा, हिमाचल प्रदेश के स्थानीय संपरीक्षा विभाग द्वारा की जाएगी और उसके द्वारा ऐसी संपरीक्षा से सम्बद्ध उपगत कोई व्यय, परिषद् द्वारा हिमाचल प्रदेश के स्थानीय संपरीक्षा विभाग को सौंप दिया जाएगा तथा परिषद् उसे बोर्ड को अर्पित करेगी ।

(3) ऐसी संपरीक्षा के सम्बन्ध में, हिमाचल प्रदेश के स्थानीय संपरीक्षा विभाग के वही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार होंगे जैसे हिमाचल प्रदेश के महालेखाकार को सरकारी लेखों की संपरीक्षा के सम्बन्ध में हैं और विशेषतया परिषद् की पुस्तकों, लेखों, सम्बद्ध वाउचरों, दस्तावेजों और कागजपत्रों को प्रस्तुत किए जाने की मांग का अधिकार होगा ।

(4) हिमाचल प्रदेश के स्थानीय संपरीक्षा विभाग द्वारा यथा प्रमाणित, उस पर संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ परिषद् के लेखे, परिषद् द्वारा बोर्ड को वार्षिक रूप में अर्पित किए जाएंगे ।

23. (1) धारा 22 में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार आदेश द्वारा, परिषद् के लेखों से सम्बन्धित किसी विशेष संव्यवहार या वर्ग या संव्यवहार की आवश्यकताओं या विशेष अवधि के लिए, ऐसे व्यक्ति या अभिकरण द्वारा जैसे वह ठीक समझे, विशेष संपरीक्षा संचालित करवा सकेगी ।

लेखों की विशेष संपरीक्षा ।

(2) जहाँ उप-धारा (1) के अधीन आदेश किया जाता है, परिषद्, संपरीक्षा के लिए ऐसे लेखे प्रस्तुत करेगी या करवाएगी और उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त किए गए व्यक्ति या अभिकरण को, ऐसी सूचना जैसी उक्त व्यक्ति या अभिकरण संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए अपेक्षा करे, देगी ।

वार्षिक
रिपोर्ट।

24. परिषद् का सदस्य-सचिव, वित्तीय वर्ष के अवसान की तारीख से तीन मास के भीतर परिषद् के क्रियाकलापों की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसकी एक प्रति बोर्ड तथा सरकार को अग्रेषित करेगा।

अध्याय-4

पर्यटन इकाई, यात्रा अभिकर्ता, गाइड और साहसिक खेल-कूद ऑपरेटर का रजिस्ट्रीकरण

पर्यटन इकाई
का रजिस्ट्री-
करण।

25. (1) पर्यटन इकाई चलाने के लिए आशयित प्रत्येक व्यक्ति, रजिस्ट्रीकरण के लिए, पर्यटन इकाई चलाने से पूर्व, विहित प्राधिकारी को विहित रीति में आवेदन करेगा :

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख पर हिमाचल प्रदेश राज्य के भीतर, पहले से ही पर्यटन इकाई चलाने वाला कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से नब्बे दिन के भीतर रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगा :

परन्तु यह और कि पर्यटन इकाई का संचालन करने वाला कोई व्यक्ति, जो पर्यटन इकाई में कोई परिवर्तन या परिवर्धन करता है, ऐसे परिवर्तन या परिवर्धन की तारीख से नब्बे दिन के भीतर नए रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन किए गए प्रत्येक आवेदन का, आवेदन प्राप्त होने की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर, निपटारा किया जाएगा, ऐसा न होने पर, आवेदन को रजिस्ट्रीकरण के लिए स्वीकृत किया गया समझा जाएगा।

(3) कोई भी व्यक्ति तब तक पर्यटन इकाई नहीं चलाएगा, जब तक कि उसे इस अधिनियम के उपबन्ध के अनुरूप रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाता है।

यात्रा अभि-
कर्ता या
गाइड का
रजिस्ट्री-
करण।

26. (1) कोई भी व्यक्ति तब तक पर्यटन अभिकर्ता या गाइड के रूप में कार-बार नहीं करेगा, जब तक कि वह इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार रजिस्ट्री-कृत नहीं हो जाता :

परन्तु कोई व्यक्ति गाइड के रूप में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि वह ऐसी अर्हताएं प्राप्त नहीं कर लेता जैसी विहित की जाएं :

परन्तु यह और कि किसी विहित अर्हता के होते हुए भी, जो व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व, गाइड के रूप में कार्यरत थे, स्वयंमेव ही गाइडों के रूप में रजिस्ट्रीकृत किए जाएंगे।

(2) पर्यटन अभिकर्ता या गाइड के रूप में कार्य करने के लिए आशयित प्रत्येक व्यक्ति, इस रूप में कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व, विहित प्राधिकारी को, विहित रीति में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगा :

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख पर, हिमाचल प्रदेश राज्य में यात्रा अभिकर्ता या गाइड के रूप में काम करने वाला कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से नब्बे दिन के भीतर रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगा।

(3) इस धारा के अधीन किए गए प्रत्येक आवेदन का, आवेदन प्राप्त होने की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर निपटारा किया जाएगा, ऐसा न होने पर आवेदन को रजिस्ट्रीकरण के लिए स्वीकृत किया गया समझा जाएगा।

27. (1) कोई व्यक्ति साहसिक खेल-कूद का कारबार तब तक नहीं करेगा जब तक कि वह इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत नहीं हो जाता।

साहसिक खेल-कूद ऑपरेटर का रजिस्ट्रीकरण।

(2) साहसिक खेल-कूद संस्थान को चलाने या साहसिक खेल-कूद ऑपरेटर के रूप में कार्य करने के लिए आशयित प्रत्येक व्यक्ति, इस रूप में कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व, विहित प्राधिकारी को, विहित रीति में, रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगा।

(3) उप-धारा (2) में, किसी बात के होते हुए भी, साहसिक खेल-कूद ऑपरेटर के रूप में पहले से ही कार्यरत कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से नब्बे दिन के भीतर, रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगा।

(4) इस धारा के अधीन किए गए प्रत्येक आवेदन का, आवेदन के प्राप्त होने की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर निपटारा किया जाएगा, ऐसा न होने पर आवेदन को रजिस्ट्रीकरण के लिए स्वीकृत किया गया समझा जाएगा।

28. विहित प्राधिकारी, जब तक धारा 25, 26 और 27 के अधीन रजिस्ट्रीकरण से इन्कार नहीं किया जाता, यथास्थिति, पर्यटन इकाई या यात्रा अभिकर्ता या गाइड या साहसिक खेल-कूद ऑपरेटर के नाम और विशिष्टताओं को इस प्रयोजन के लिए बनाए गए रजिस्टर में प्रविष्टि किए जाने का निदेश देगा और, यथास्थिति, पर्यटन इकाई या यात्रा अभिकर्ता, गाइड या साहसिक खेल-कूद ऑपरेटर को विहित रीति में, रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

पर्यटन इकाई, यात्रा अभिकर्ता, गाइड और साहसिक खेल-कूद ऑपरेटर के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र।

29. विहित प्राधिकारी, इस अधिनियम के अधीन या निम्नलिखित में से किसी आधार पर, यथास्थिति, पर्यटन इकाई या यात्रा अभिकर्ता या गाइड या साहसिक खेल-कूद ऑपरेटर का रजिस्ट्रीकरण करने से इन्कार कर सकेगा,—

पर्यटन इकाई, यात्रा अभिकर्ता, गाइड और साहसिक खेल-कूद ऑपरेटर के रजिस्ट्रीकरण से इन्कार।

(क) यदि, यथास्थिति, पर्यटन इकाई ऑपरेटर या यात्रा अभिकर्ता या गाइड या साहसिक खेल-कूद ऑपरेटर, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अध्याय 14 और 16 के अधीन, या इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन या जमाखोरी, तस्करी या मुनाफाखोरी या धांधली और धोखाधियों का अपमिश्रण, या भ्रष्टाचार के निवारण का उपबन्ध करने वाली किसी विधि के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है, और उस पर अधिरोपित दण्डादेश के पर्यवेक्षण से, दो वर्ष व्यतीत नहीं हुए हैं;

(ख) यदि, यथास्थिति, पर्यटन इकाई ऑपरेटर या यात्रा अभिकर्ता या गाइड या साहसिक खेल-कूद ऑपरेटर को, सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया जाता है और उन्मोचित नहीं किया गया है;

(ग) यदि, यथास्थिति, पर्यटन इकाई ऑपरेटर या यात्रा अभिकर्ता या गाइड या साहसिक खेल-कूद ऑपरेटर का नाम धारा 30 के खण्ड (ग), (घ), (ङ) या

(छ) में उल्लिखित आधार पर रजिस्टर से हटाया गया है और ऐसे हटाए जाने की तारीख से तीन मास व्यतीत नहीं हुए हों;

(घ) यदि पर्यटन इकाई का परिसर विहित मानक के अनुरूप नहीं हो;

(ङ) यदि यात्रा अभिकर्ता या गाइड या साहसिक खेल-कूद ऑपरेटर विहित अर्हताओं में से कोई अर्हता नहीं रखता हो;

(च) यदि, यथास्थिति, पर्यटन इकाई ऑपरेटर या यात्रा अभिकर्ता या गाइड या साहसिक खेल-कूद ऑपरेटर इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा रखे जाने के लिए अपेक्षित रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र नहीं रखता हो;

(छ) यदि पर्यटन इकाई ऑपरेटर सबूत पेश करने में विफल हो जाता है कि पर्यटन इकाई की संरचना, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 के उपबन्धों के अधीन या प्रवृत्त किसी अन्य स्थानीय विधि के अधीन बनाई गई भवन बनाने सम्बन्धी उप-विधियों के अनुसार बनाई गई है; और

1977 का 12

(ज) यदि विहित प्राधिकारी की राय में, रजिस्ट्रीकरण से इन्कार करने के लिए लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने के लिए पर्याप्त आधार हो :

परन्तु रजिस्ट्रीकरण के किसी आवेदन को तब तक इन्कार नहीं किया जाएगा जब तक कि रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाता है ।

रजिस्टर से पर्यटन इकाई, यात्रा अभिकर्ता, गाइड और साहसिक खेल-कूद ऑपरेटर का नाम हटाना ।

30. विहित प्राधिकारी, निम्नलिखित में से किसी आधार पर, लिखित आदेश द्वारा रजिस्टर से, यथास्थिति, पर्यटन इकाई या यात्रा अभिकर्ता या गाइड या साहसिक खेल-कूद ऑपरेटर के नाम को हटा सकेगा और धारा 28 के अधीन जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र को रद्द कर सकेगा, अर्थात्,—

(क) यदि, यथास्थिति, पर्यटन इकाई ऑपरेटर या यात्रा अभिकर्ता या गाइड या साहसिक खेल-कूद ऑपरेटर, पर्यटन इकाई को चलाना छोड़ देता है या यात्रा अभिकर्ता या गाइड या साहसिक खेल-कूद ऑपरेटर, जिस के लिए वह रजिस्ट्रीकृत है, का कार्य करना छोड़ देता है ;

(ख) यदि, यथास्थिति, पर्यटन इकाई ऑपरेटर या यात्रा अभिकर्ता या गाइड या साहसिक खेल-कूद ऑपरेटर, भारतीय दंड संहिता, 1860 के अध्याय 14 और 16 के अधीन या इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन या जमाखोरी, तस्करी या मुनाफाखोरी या खाल और औषधियों का अपमिश्रण या भ्रष्टाचार के निवारण का उपबन्ध करने वाली किसी विधि के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है और उस पर अधिरोपित दण्डादेश के पर्यवसान से, दो वर्ष व्यतीत नहीं हुए हैं ;

1860 का 45

(ग) यदि, यथास्थिति, पर्यटन इकाई ऑपरेटर या यात्रा अभिकर्ता या गाइड या साहसिक खेल-कूद ऑपरेटर को सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय

द्वारा दिवालिया घोषित किया गया है, और उन्मोचित नहीं किया गया है ;

- (घ) यदि, यथास्थिति, पर्यटन इकाई ऑपररेटर या यात्रा अभिकर्ता या गाइड या साहसिक खेल-कूद ऑपररेटर, इस अधिनियम के किसी उपबन्ध या तद्धीन बनाए गए नियमों का अनुपालन करने में असफल रहता है ;
- (ङ) यदि पर्यटन इकाई ऑपररेटर ऐसे ठहरने वाले को जो उसकी पर्यटन इकाई के तथा पार्श्वस्थ भवन के, अन्तःवासियों के लिए न्यूसेंस बन रहा हो, निकालने में असफल रहता है या पर्यटन इकाई में जानबूझ कर रखता है ;
- (च) यदि, यथास्थिति, पर्यटन इकाई ऑपररेटर या यात्रा अभिकर्ता या गाइड या साहसिक खेल-कूद ऑपररेटर के विरुद्ध अनाचार की कोई शिकायत प्राप्त होती है और साबित होती है ;
- (छ) यदि पर्यटन इकाई ऑपररेटर, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 के अधीन गठित विकास प्राधिकरण या स्थानीय विधियों के अधीन गठित किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण के अनुमोदन के बिना संरचनात्मक परिवर्तन करता है ;
- (ज) यदि, यथास्थिति, पर्यटन इकाई ऑपररेटर या यात्रा अभिकर्ता या गाइड या साहसिक खेल-कूद ऑपररेटर ने, दुर्व्यपदेशन या कपट द्वारा रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त किया है ;
- (झ) यदि साहसिक खेल-कूद ऑपररेटर, सुरक्षा के लिए विहित स्तर के अनुसार उपस्कर, जनशक्ति और अन्य सुविधाएं नहीं रखता है ; और
- (ञ) यदि साहसिक खेल-कूद ऑपररेटर, सुरक्षा उपाय जैसे विहित किए जाएं, के विषय में पूर्वावधानी नहीं लेता है :

परन्तु इस धारा के अधीन, यथास्थिति, किसी पर्यटन इकाई या यात्रा अभिकर्ता या गाइड या साहसिक खेल-कूद ऑपररेटर का नाम रजिस्टर से हटाने से पूर्व, विहित प्राधिकारी, यथास्थिति, पर्यटन इकाई या यात्रा अभिकर्ता या गाइड या साहसिक खेल-कूद ऑपररेटर को वे आधार दर्शाते हुए, जिन पर उसे सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् कार्रवाई करना प्रस्तावित है, नोटिस देगा ।

31. विहित प्राधिकारी,—

पर्यटन
इकाई का
वर्गीकरण ।

विहित रीति में गठित की जाने वाली समिति के परामर्श से,—

- (क) पर्यटन इकाईयों को विभिन्न श्रेणियों, जैसी विहित की जाएं, में वर्गीकृत कर सकेगा ; और
- (ख) वास-सुविधा के बारे में प्रत्येक कमरे में ठहराए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या नियत कर सकेगा ।

उचित दरें
अधिसूचित
करना।

32. (1) विहित प्राधिकारी, पर्यटन इकाई द्वारा यथा विनिर्दिष्ट पर्यटन इकाईयों के वर्ग और भोजन वास सुविधा तथा सेवा गुणवत्ता के स्तर की उचित दरें और सेवा के प्रभार, यदि कोई हों, जिन्हें पर्यटकों या ग्राहकों से "सीज़न" और "ऑफ सीज़न" के दौरान खान-पान या ठहरने के लिए प्रभारित किया जा सकेगा, अधिसूचित करेगा :

परन्तु प्रभारित की जाने वाली दर के बारे में विवाद की दशा में, धारा 31 के अधीन गठित समिति का विनिश्चय अन्तिम होगा :

परन्तु यह और कि ठहरने के लिए दरें, प्रत्येक कमरे या विनिर्दिष्ट वास-सुविधा और ठहराए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, अधिसूचित की जाएंगी।

(2) विहित प्राधिकारी, उचित दरें जिन्हें यात्रा अभिकर्ता या गाइड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा, जो उसके द्वारा उसे इस रूप में लगाने वाले व्यक्ति को दी गई सेवाओं के लिए उससे (व्यक्ति से) प्रभारित कर सकेगा, अधिसूचित करेगा।

(3) विहित प्राधिकारी, साहसिक खेल-कूद और अन्य सुविधाओं के स्तर के अनुरूप उचित दरें, जो साहसिक खेल-कूद ऑपरेटर द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, जो पर्यटकों से उनके द्वारा प्रभारित की जा सकेंगी, अधिसूचित करेगा।

उचित
दरों का
पुनरीक्षण।

33. विहित प्राधिकारी, समय-समय पर धारा 32 के अधीन अधिसूचित उचित दरों का पुनरीक्षण कर सकेगा।

उचित दरें
अधिसूचित
करना, जब
तक कि
विहित प्राधि-
कारी द्वारा
अधिसूचित
न की जाएं।

34. ऐसे समय तक, जब तक कि विहित प्राधिकारी धारा 32 के अधीन यथा अपेक्षित उचित दरें और प्रत्येक कमरे में ठहराए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या अधिसूचित नहीं करता, यथास्थिति, पर्यटन इकाई ऑपरेटर या यात्रा अभिकर्ता या गाइड या साहसिक खेल-कूद ऑपरेटर उचित दरों को अधिसूचित करेगा और प्रत्येक वर्ष की 31 जुलाई तक विहित प्राधिकारी को उन्हें सूचित करेगा तथा "सीज़न" और "ऑफ सीज़न" की अवधि के लिए पथक दरें नियत की जाएंगी और ऐसी दरें उस वर्ष के प्रथम अवतूबर से आगामी वर्ष के तीस सितम्बर तक प्रभावी होंगी।

सूचना का
प्रदर्शन।

35. जहां, विहित प्राधिकारी ने धाराओं 32 और 33 के अधीन उचित दरें और प्रत्येक कमरे में ठहरने वाले व्यक्तियों की संख्या अधिसूचित या पुनरीक्षित की हों या उस दशा में जहां विहित प्राधिकारी ने उचित दरें अधिसूचित नहीं की हों, वहां, यथास्थिति, पर्यटन इकाई ऑपरेटर या यात्रा अभिकर्ता या गाइड या साहसिक खेल-कूद ऑपरेटर, उचित दरें और प्रत्येक कमरे में वास-सुविधा दिए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या की सूचना, पर्यटन इकाई, यात्रा अभिकर्ता, गाइड या साहसिक खेल-कूद ऑपरेटर के कारवार के परिसर में सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित करेगा और पर्यटन इकाई ऑपरेटर का अभिकर्ता, विहित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित ऐसी सूचना की प्रति अपने पास भी रखेगा।

उचित दरों से
अधिक वसूलीय
प्रभार।

36. (1) किसी करार के प्रतिकूल होते हुए भी, यथास्थिति, कोई पर्यटन इकाई ऑपरेटर या यात्रा अभिकर्ता या गाइड या साहसिक खेल-कूद ऑपरेटर, नियत उचित दरों में अधिक कोई रकम प्रभारित नहीं करेगा।

(2) ठहरने वाले व्यक्ति या किसी व्यक्ति द्वारा नियत उचित दरों से अधिक संदत्त की गई राशि, ठहरने वाले या किसी व्यक्ति को विहित प्राधिकारी के माध्यम से, यथास्थिति, पर्यटन इकाई ऑपरेटर या यात्रा अभिकर्ता या गाइड या साहसिक खेल-कूद ऑपरेटर द्वारा प्रत्यर्पणीय होगी।

37. यथास्थिति, कोई भी पर्यटन इकाई ऑपरेटर या यात्रा अभिकर्ता या गाइड या साहसिक खेल-कूद ऑपरेटर, ठहरने वाले व्यक्ति या किसी व्यक्ति को, जब तक कि वह नियत उचित दर का संदाय करता है या संदाय करने के लिए तैयार और तत्पर है और अपने करार की अन्य शर्तों का, जहाँ तक वह इस अधिनियम के उपबन्धों से संगत है, पालन और कार्यान्वयन करता है, बेदखल या किसी अन्य सेवा से इन्कार नहीं करेगा।

यदि उचित दर संदत्त की गई हो तो बेदखल न किया जाना।

38. (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, पर्यटन इकाई ऑपरेटर उसके द्वारा दी गई वास-सुविधा का, विहित प्राधिकारी से उम प्रभाव का आदेश प्राप्त करके, कब्जा लेने का हकदार होगा कि,—

पर्यटन इकाई ऑपरेटर कब कब्जा वापस ले सकेगा।

(क) ठहरने वाला व्यक्ति ऐसे आचरण का दोषी है जो न्यूसैम है या किसी अन्य ठहरने वाले व्यक्ति के लिए कोई क्षोभ पैदा करता है; या

(ख) ठहरने वाला व्यक्ति वास-सुविधा प्रभार संदत्त करने में असफल हो गया है; या

(ग) ठहरने वाला व्यक्ति वास-सुविधा के बारे में किए गए करार की अवधि की समाप्ति पर, उसे खाली करने में असफल रहा है :

परन्तु इस धारा के अधीन आदेश जारी करने से पूर्व, विहित प्राधिकारी, संक्षिप्त जांच कर सकेगा और संक्षिप्त रीति में समुचित आदेश पारित करेगा:

परन्तु यह और कि विहित प्राधिकारी के आदेश द्वारा व्यक्ति कोई पक्षकार, सम्बद्ध जिला के जिला मजिस्ट्रेट को अपील कर सकेगा, जो इसे संक्षिप्त रीति में निपटाएगा।

(2) यदि ठहरने वाला व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उप-धारा (1) के अधीन आदेश पारित हुआ है, उक्त आदेशों की अनुपालना नहीं करता है, तो विहित प्राधिकारी, आदेश को लागू करवाने के लिए पुलिस की सहायता ले सकेगा और प्रत्येक पुलिस अधिकारी उक्त आदेश की अनुपालना हेतु सहायता करेगा।

39. यथास्थिति, पर्यटन इकाई ऑपरेटर या यात्रा अभिकर्ता या गाइड या साहसिक खेल-कूद ऑपरेटर, ठहरने वाले व्यक्ति और अन्य ग्राहकों को ब्योरे-वार त्रिल पेश करेगा और अभिस्वीकृति के रूप में सभी संदायों की रसीद देगा।

पर्यटन इकाई ऑपरेटर, यात्रा अभिकर्ता, गाइड और साहसिक खेल-कूद ऑपरेटर द्वारा बिलों का ब्योरेवार पेश किया जाना।

पर्यटन इकाई
ऑपरेटर
कब विशेष
दर पर,
बुकिंग का
पुष्टिकरण
कर सकेगा।

40. यदि पर्यटन इकाई ऑपरेटर विशिष्ट दर पर बुकिंग का पुष्टिकरण करता है, तो उस व्यक्ति जिसके लिए वास-सुविधा बुक की गई है, के पहुंचने के समय चाहे वास सुविधा केवल उच्च दरों पर ही उपलब्ध हो, तो भी उसे उसी दर पर देगा।

प्रवेश, निरी-
क्षण, अभि-
ग्रहण की
शक्ति और
पर्यटन इकाई
ऑपरेटर,
इत्यादि द्वारा
मांछिकी
आंकड़े
प्रदत्त करना।

41. (1) विहित प्राधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का, यथास्थिति, पर्यटन इकाई ऑपरेटर या यात्रा अभिकर्ता या गाइड या साहसिक खेल-कूद ऑपरेटर द्वारा क्रियान्वयन नहीं किया गया है, तो वह यात्रा अभिकर्ता या गाइड या साहसिक खेल-कूद ऑपरेटर की पर्यटन इकाई या कारबार के परिसर में प्रवेश कर सकेगा और पूर्व सूचना से या के बिना, समस्त लेखों, रजिस्ट्रों, दस्तावेजों और अन्य पुस्तकों का निरीक्षण कर सकेगा।

(2) यदि विहित प्राधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के पास संदेह करने का कारण है कि, यथास्थिति, कोई पर्यटन इकाई ऑपरेटर या यात्रा अभिकर्ता या गाइड या साहसिक खेल-कूद ऑपरेटर, इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का अपवंचन करने का प्रयत्न कर रहा है या अपवंचन किया है, तो ऐसा प्राधिकारी या अधिकारी, कारणों को अभिलिखित करते हुए, यथास्थिति, ऐसे ऑपरेटर या यात्रा अभिकर्ता या गाइड या साहसिक खेल-कूद ऑपरेटर के ऐसे लेखों, रजिस्ट्रों, दस्तावेजों या अन्य पुस्तकों को, जैसा आवश्यक हो, अभिगृहीत कर सकेगा और उसके लिए रसीद देगा तथा उसे तब तक रखेगा, जब तक परीक्षण या इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो।

(3) यथास्थिति, प्रत्येक पर्यटन इकाई ऑपरेटर या यात्रा अभिकर्ता या गाइड या साहसिक खेल-कूद ऑपरेटर, विहित प्राधिकारी को सम्बद्ध इकाई के पर्यटकों के अन्तर्वाह और नियोजित कर्मचारियों के बारे में प्रत्येक मास की अनुगामी दस तारीख तक आंकड़े उपलब्ध करवाएगा।

यात्रा
अभिकर्ता,
गाइड और
साहसिक
खेल-कूद
ऑपरेटर
द्वारा "टिप"
(बखशीश)
इत्यादि न
मांगना।

42. यथास्थिति, यात्रा अभिकर्ता या गाइड या साहसिक खेल-कूद ऑपरेटर उसे नियुक्त करने वाले किसी व्यक्ति या किसी पर्यटक इकाई ऑपरेटर, जिसकी पर्यटन इकाई में ऐसा व्यक्ति निवास करता है या निवास करने का आशय रखता है, से धारा 32 के अधीन यथा नियत दरों के सिवाय, कोई "टिप" (बखशीश), उपहार, उपहार या कमीशन की मांग नहीं करेगा।

बीमा।

43. साहसिक खेल-कूद ऑपरेटर, उसकी सेवाएं लेने वाले व्यक्तियों को, जैसा विहित किया जाए, बीमा रक्षण की व्यवस्था करेगा।

अध्याय-5

अपील और पुनरीक्षण

44. (1) उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन, इस अधिनियम के अधीन अपील।
विहित प्राधिकारी के प्रत्येक आदेश के विरुद्ध अपील, सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने
वाले अपील प्राधिकारी को होगी।

(2) प्रत्येक ऐसी अपील, आदेश की संसूचना की तारीख से नब्बे दिन के भीतर
प्रस्तुत की जाएगी :

परन्तु अपील प्राधिकारी, उक्त नब्बे दिन की अवधि के अवसान के पश्चात् भी
अपील ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर
अपील करने से युक्तियुक्त कारणों द्वारा निवारित हुआ था।

(3) अपीलार्थी को, अधिवक्ता या सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा, प्रतिनिधित्व
किए जाने का अधिकार होगा तथा विहित प्राधिकारी का ऐसे अधिकारी या व्यक्ति
द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा सकेगा, जिसे विहित प्राधिकारी नियुक्त करे।

(4) किसी अपील की प्राप्ति पर, अपील प्राधिकारी, अपीलार्थी को सुनवाई का
युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् और ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी वह
उचित समझता हो और उसके कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात्, ऐसा आदेश
जैसा वह उचित समझे, पारित करेगा।

45. सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाला पुनरीक्षण प्राधिकारी, स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण।
या व्यथित पक्षकार द्वारा किए गए आवेदन पर, अपील प्राधिकारी द्वारा निपटाए
गए मामले के अभिलेखों को, अपील प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के सही-
करण, वैधता या औचित्य के बारे में, अपना समाधान करने के उद्देश्य से, मंगवा सकेगा
तथा तदुपरि ऐसा आदेश पारित करेगा जो वह उचित समझे और ऐसा आदेश अन्तिम
होगा :

परन्तु पुनरीक्षण के लिए ऐसा आवेदन, अपील प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश
की संसूचना की तारीख से तीन मास की अवधि के अवसान के पश्चात् ग्रहण
नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और कि पुनरीक्षण प्राधिकारी स्वप्रेरणा से, किसी प्राधिकारी द्वारा
विनिश्चित किए गए या उसके सम्मुख लम्बित किसी मामले का अभिलेख
मंगवा सकेगा और ऐसा आदेश, जैसा वह उचित समझे, पारित कर सकेगा :

परन्तु यह और कि इस धारा के अधीन व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने
वाला आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा, जब तक उसे व्यक्तिगत
रूप से या अधिवक्ता द्वारा या सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा
सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं किया जाता।

अध्याय-6

अपराध और शास्तियां

रजिस्ट्रीकरण में व्यतिक्रम के लिए शास्ति । 46. इस अधिनियम के अधीन उचित रजिस्ट्रीकरण के बिना या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के उल्लंघन में, पर्यटन इकाई या यात्रा अभिकर्ता या गाइड या साहसिक खेलकूद या पर्यटन व्यापार से सम्बन्धित कोई अन्य कारबार करने वाला कोई व्यक्ति, छह मास से अनधिक अवधि के कारावास से या दस हजार रुपए से अनधिक जुर्माने से, या दोनों से, और यदि उल्लंघन जारी रहता हो तो, कम से कम दो सौ रुपए प्रतिदिन और अधिक से अधिक दो हजार रुपए प्रतिदिन, जब तक व्यतिक्रम जारी रहता है, के जुर्माने से दण्डनीय होगा ।

मिथ्या कथन के लिए शास्ति । 47. इस अधिनियम के अधीन कथन देने के लिए अपेक्षित कोई व्यक्ति, यदि जानबूझ कर मिथ्या कथन करता है या विहित प्राधिकारी को भुलावा देने के लिए किसी सारभूत तथ्य को छुपाता है, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी या दो हजार रुपए से अनधिक जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

प्रमाण-पत्र का बिना अनुज्ञा के समनुदेशित न किया जाना । 48. कोई व्यक्ति जो, विहित प्राधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना इस अधिनियम के अधीन जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र को उधार देता है, हस्तान्तरित या समनुदेशित करता है, तो वह कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या दस हजार रुपए से अनधिक जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

व्यक्तियों के मांगने पर प्रमाण-पत्र दिखाया जाना । 49. (1) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई व्यक्ति, किसी भी समय, निम्नलिखित में से किसी व्यक्ति के मांग करने पर, अपना रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र निम्नलिखित को दिखाएगा, अर्थात् :—

(क) विहित प्राधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी ; और

(ख) सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी प्राधिकारी या निदेशक, पर्यटन हिमाचल प्रदेश द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी ; और

(ग) वास्तविक ग्राहक ।

(2) कोई व्यक्ति, जो प्राधिकृत व्यक्तियों में से किसी द्वारा मांगने पर अपना प्रमाण-पत्र दिखाने या इसे पढ़ने की अनुज्ञा देने से इन्कार करता है, तो वह पांच हजार रुपए से अनधिक जुर्माने से, दण्डनीय होगा ।

अनाचार के लिए शास्ति । 50. कोई व्यक्ति जो अनाचार करता है या इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध जिसके लिए कोई भी विनिर्दिष्ट शास्ति उपबन्धित नहीं की गई है, का उल्लंघन करता है, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या दस हजार रुपए से अनधिक जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

51. यदि कोई व्यक्ति, विहित अधिकारी या उसके द्वारा इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में या द्वारा, उसे प्रदत्त या उसको अधिरोपित किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने या कर्तव्यों का पालन करने हेतु प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के कर्तव्यों के उन्मोचन में, जानबूझ कर कोई बाधा डालता है या कोई प्रतिरोध करता है अथवा अन्यथा विघ्न डालता है, तो वह कारावास से जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या एक हजार रुपये से अनधिक जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

विधियुक्त प्राधिकारियों को बाधा पहुंचाना।

52. इस अधिनियम के अधीन सभी अपराधों पर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या उच्च न्यायालय द्वारा विशेषतया प्राधिकृत प्रथम श्रेणी के किसी अन्य मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षेपतः विचारण किया जाएगा और ऐसे विचारण पर जहां तक हो सके, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 262 से 265 (दोनों का सम्मिलित करके) के उपबन्ध लागू होंगे :

मामलों का संक्षेपतः विचारण करने की न्यायालयों की शक्ति।

परन्तु, इस धारा के अधीन, विचारण प्रारम्भ होने पर या उसके संक्षेपतः विचारण के दौरान, जब मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि मामले की प्रकृति ऐसी है कि किसी कारण से उसका संक्षेपतः विचारण अवाञ्छनीय है, तो मजिस्ट्रेट, पक्षकारों की सुनवाई के पश्चात्, उस आशय का आदेश अधिलिखित करेगा और तत्पश्चात् किसी साक्षी को जिसका परीक्षण किया गया है, पुनः बुलाएगा और उपर्युक्त संहिता में उपबंधित रीति में मामले की सुनवाई या पुनः सुनवाई करने के लिए अग्रसर होगा।

53. इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए, विहित प्राधिकारी या उस द्वारा या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा की गई शिकायत के सिवाय, किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई अभियोजन संस्थित नहीं किया जाएगा।

कार्यवाहियों संस्थित करना।

54. विहित प्राधिकारी को, इस अधिनियम के अधीन आवेदन पर सुनवाई करते समय, निम्नलिखित मामलों के बारे में, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी,—

विहित प्राधिकारी की, साक्षियों तथा अन्य व्यक्तियों को समन करने और हाजिर करवाने की शक्ति।

(क) परिवादी या ऐसे व्यक्ति जिसके विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन परिवाद किया गया है को, और इस सम्बन्ध में उससे (परिवाद से) अपेक्षित साक्षियों को समन करने और हाजिर करवाने ;

(ख) किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करने ; और

(ग) शपथ पर साक्षियों का परीक्षण करने ;

और किसी भी व्यक्ति को, जिसका साक्ष्य सारभूत प्रतीत होता है, स्वप्रेरणा से समन और उसका परीक्षण कर सकेगा।

55. (1) विहित प्राधिकारी, किसी ऐसे व्यक्ति जिस पर उसे इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध करने का युक्तियुक्त संदेह हो, से ऐसे अपराध के शमन के रूप में कोई राशि स्वीकार कर सकेगा और ऐसे प्राप्त की गई राशि से, ऐसे व्यक्ति को जिसके विरुद्ध अपराध किया गया हो, उस विस्तार तक, जिसे विहित प्राधिकारी युक्तियुक्त समझे, प्रतिकर दे सकेगा।

अपराधों का शमन।

(2) अपराध के शमन पर, उसके बारे में अभियुक्त के विरुद्ध आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी और यदि उसके विरुद्ध न्यायालय में पहले से कोई कार्यवाही संस्थित की गई हो, तो शमन दोषमुक्ति के रूप में प्रभावी होगा।

अध्याय-7

प्रकीर्ण

परिवर्तनों की
अधिसूचना।

56. (1) जब कोई पर्यटन इकाई, जिसके लिए किसी व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र लिया गया है, उत्तराधिकार द्वारा या अन्यथा किसी दूसरे व्यक्ति को न्यागत हो जाती है, या इस अधिनियम के अधीन इस विषय में रजिस्टर में की गई किसी विशिष्ट प्रविष्टि में परिवर्तन हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति, ऐसे न्यागत या परिवर्तन की तारीख से तीस दिन के भीतर, ऐसे तथ्य को लिखित रूप में विहित प्राधिकारी को अधिसूचित करेगा।

(2) विहित प्राधिकारी, इस प्रयोजन के लिए बनाए रखे गए रजिस्टर और रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में आवश्यक परिवर्तन करेगा।

(3) उप-धारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, विहित प्राधिकारी, रजिस्टर से ऐसे व्यक्ति जिसके पक्ष में प्रमाण-पत्र जारी किया गया था का नाम हटा सकेगा और यदि उत्तरवर्ती इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए जाने का पात्र नहीं है तो रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र को रद्द कर सकेगा।

रजिस्ट्रीकरण
प्रमाण-पत्र
वापस
करना।

57. इस अधिनियम के अधीन जब रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया जाए तो प्रमाण-पत्र का धारक व्यक्ति, रद्दकरण आदेश की विहित रीति में, तारीख की तारीख से सात दिन के भीतर, विहित प्राधिकारी को इसे वापस करेगा।

डुप्लीकेट
प्रमाण-पत्र।

58. इस अधिनियम के अधीन जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र यदि गम, क्षतिग्रस्त या नष्ट हो जाता है, तो विहित प्राधिकारी, ऐसे प्रमाण-पत्र के धारक व्यक्ति द्वारा इस निमित्त किए गए आवेदन पर और विहित फीस के संदाय पर, डुप्लीकेट प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

प्रमाण-पत्र
का नवी-
करण।

59. इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत पर्यटन इकाई ऑपरेटर या यात्रा अभिकर्ता या गाइड या साहसिक खेल-कूद ऑपरेटर, विहित प्राधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के पश्चात्, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र को नवीकृत करेगा और नवीकृत अनुज्ञप्ति फीस, जैसी विहित की जाए, भी संदत्त करेगा।

रजिस्ट्रीकरण
प्रमाण-पत्र
का प्रदर्शित
रखा जाना।

60. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र, इस के धारक व्यक्ति द्वारा, उसके कारबार के मुख्य स्थान पर सहज-दृश्य स्थान पर रखा जाएगा और यदि उसके कारबार का मुख्य स्थान न हो या वह किसी विशेष स्थान से अन्यथा कारबार चलाता हो, तो वह इसे रखा जाना। अपने पास रखेगा।

1860 का
45

61. इस अधिनियम के अधीन विहित प्राधिकारी के समक्ष सभी कार्यवाहियां भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 193 और 228 के प्रयोजन के लिए न्यायिक कार्यवाहियां समझी जाएंगी।

विहित प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाहियों का न्यायिक कार्यवाहियां होना।

62. इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही सरकार के अथवा किसी व्यक्ति के विरुद्ध न होगी।

परित्याग।

63. सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के सभी या कोई उपबन्ध, ऐसे अपवादों, अनुकूलकरणों या उपांतरणों सहित, जैसे आवश्यक समझे जाएं, हिमाचल प्रदेश राज्य में बह्य फोटो-खींचने, गृह-नौका, डोंगी, स्नानागार नौका (बेदिंग बोट), शिकारे, डांडियों, पिट्टुओं, टट्टुओं को किराए पर देने या उन्हें चलाने के कारबार में लगे व्यक्तियों अथवा ऐसे अन्य व्यक्तियों, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, को लागू होंगे और विहित प्राधिकारी, की जाने वाली सेवाओं के लिए प्रभारित की जाने वाली दरें नियत कर सकेगा।

अन्य व्यक्तियों को अधिनियम को लागू करने की सरकार की शक्ति।

64. (1) सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी।

नियम बनाने की शक्ति।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा :—

(क) पर्यटन इकाई ऑपरेटरों, यात्रा अभिकर्ताओं, गाइडों और साहसिक खेल-कूद ऑपरेटरों द्वारा कारबार के संचालन के लिए, रजिस्ट्रारों, पुस्तकों और प्ररूपों का बनाए रखा जाना ;

(ख) रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन और रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र का प्ररूप ;

(ग) रजिस्ट्रीकरण, नवीकरण और डुप्लीकेट प्रमाण-पत्र के जारी करने के लिए फीस ;

(घ) इस अधिनियम के अधीन नोटिस देने की रीति ;

(ङ) पर्यटन इकाईयों का वर्गीकरण ;

(च) पर्यटन इकाई ऑपरेटर, यात्रा अभिकर्ता, गाइड और साहसिक खेल-कूद ऑपरेटर के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए अर्हता ;

(छ) साहसिक खेल-कूद के संचालन में अपनाए जाने वाले सुरक्षा उपाय और मानक तथा प्रदान की जाने वाली सुविधाएं ;

- (ज) विभिन्न प्रकार की पर्यटन इकाईयों में स्वास्थ्यकर और सफाई, अपशिष्ट निपटान और न्यूनतम सुविधाओं को बनाए रखने के लिए मानक ;
- (झ) रजिस्टर से हटाए गए, पर्यटन इकाई, यात्रा अभिकर्ता, गाइड और साहसिक खेल-कूद ऑपरेटर के नाम और पते प्रकाशित करने की रीति ;
- (ञ) वह रीति जिसमें नियत उचित दरें प्रदर्शित की जाएंगी, विहित प्राधिकारी को टिकटों के प्रकार, और जारी की जाने वाली रसीदें, उसके लेखे और विवरणी प्रस्तुत करना और बनाए रखना, अनुज्ञप्ति फीस, नवीकरण फीस और अन्य देयों का संग्रहण और निक्षेप ;
- (ट) प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए प्रक्रिया, पाठ्य-विवरण, कर्मचारी-वृन्द, उपस्कर और भवनों के मानक ; और
- (ठ) वह स्थान जहां विहित प्राधिकारी इस अधिनियम के अधीन जांच करेगा, और इस अधिनियम के अधीन अभिव्यक्त रूप में विहित किए जाने वाले सभी विषय ।
- (3) इस धारा के अधीन बनाए गए सभी नियम, पूर्व प्रकाशन की शर्त के अध्वधीन होंगे ।

निरसन और
व्यावृत्ति यां ।

65. हिमाचल प्रदेश पर्यटन व्यवसाय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1988 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है :

परन्तु उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अधीन जारी की गई किसी अधिसूचना, मंजूर किया गया प्रमाण-पत्र या अनुज्ञा या प्रारम्भ या जारी की गई कार्य-वाहियों सहित, की गई कोई बात या कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

पर्यटन को एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाकलाप के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह स्थानीय लोगों के ष्पाजन और देश के लिए विदेशी मुद्रा उपाजित करने का मुख्य स्रोत है। राज्य में पर्यावरण के कारण, हिमाचल प्रदेश में पर्यटन की विस्तृत संभावना है क्योंकि यह सांस्कृतिक और भौगोलिक रूप में धारणीय है। इसलिए इसे व्यापक स्तर पर रोजगार के अवसरों के सृजन द्वारा राज्य के लोगों के लिए समृद्धि लाने का एक प्रभावशाली साधन समझा जा रहा है। पर्यटन, पर्यटकों को अपेक्षित सुख-सुविधाएं और सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए स्थानीय लोगों और प्राइवेट सेक्टर की सहभागिता की अपेक्षा करता है। विद्यमान हिमाचल प्रदेश पर्यटन व्यवसाय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1988 में, पर्यटन के उन्नयन के लिए सहभागिता विरचना का अभाव है अतः पर्यटन के उन्नयन तथा हिमाचल प्रदेश को आकर्षक और सुरक्षित पर्यटन गन्तव्य बनाने हेतु स्थानीय लोगों और प्राइवेट सेक्टर की बृहतर सहभागिता प्राप्त करने के लिए पर्यटन विकास बोर्ड का गठन करना प्रस्तावित है। पर्यटन विकास बोर्ड के अधिकांश सदस्यों को विशेषज्ञों और पर्यटन उद्योग के विभिन्न हितबद्ध समूहों जैसे कि होटल मालिकों, यात्रा अभिकर्ताओं, साहसिक खेलकूद ऑपरेटरों, परिव्राहकों इत्यादि में से लिया जाना प्रस्तावित है। बोर्ड से, पर्यटन सेक्टर की सेवाओं में श्रेष्ठता लाने के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन करने हेतु मानव संसाधन प्रयत्नों का जिम्मा लेना भी प्रत्याशित होगा। बोर्ड पर्यटकों को विपणन और सुविधाएं तथा सुख-सुविधाओं के लिए सामान्य सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु साधन जुटाएगा। पर्यटकों की निरन्तर बढ़ती संख्या को सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा उन्हें पर्यावरण अवक्रमण से बचाने के लिए पर्यटन गन्तव्यों (स्थलों) को विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। पर्यटन उद्योग से बहुसंख्यक प्रतिनिधित्व के साथ पर्यटन, क्रियाकलापों को ऐसी रीति में रेखांकित (प्लान) मार्गदर्शित, निष्पादित और विनिर्दिष्ट करने के लिए, विभिन्न स्थानों पर पर्यटन विकास परिषदों का गठन करने का प्रस्ताव है ताकि पर्यटन पर्यावरणिक रूप से धारणीय बन जाए तथा स्थानीय संस्कृति के सामंजस्य में हो। ये निकाय पर्यटक गन्तव्यों (स्थलों) के उन्नयन और रखरखाव में स्थानीय निकायों के प्रयासों को पूरित करेंगे। ये सरकार तथा पर्यटन विकास बोर्ड द्वारा अधिकथित समग्र नीति ढांचे के अन्तर्गत कार्य करेंगे तथा पर्यटक को और पर्यटन उद्योग को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सेवाएं उपलब्ध करवा कर अपने क्षेत्रों में साधन जनक प्रयास करेंगे। अतः इन निकायों का गठन करने हेतु एक नया अध्याय जोड़ना प्रस्तावित है।

यह भी अनुभव किया गया है कि निकट भविष्य में, होटलों और रेस्तराओं से अन्यथा नई प्रकार की पर्यटन इकाईयों का आगमन हो रहा है या उनके आगमन की सम्भावना है तथा उनके उन्नयन, पर्यावरण और सुरक्षा के मानकीकरण तथा बोर्ड और परिषद के पर्यटन उन्नयन के प्रयासों का अभिन्न अंग बनाने के लिए कतिपय दिशा निर्देशों का उपबन्ध करना आवश्यक है। आमोद पाकों, पर्यटन प्रशिक्षण संस्थानों, हाऊस बोटों, मोटर काफिलों इत्यादि जैसी इकाईयों को सम्मिलित करने के लिए अधिनियम के कार्यक्षेत्र का विस्तार करने की आवश्यकता है। ऐसी इकाईयों के, उनके संचालन में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानकों को प्रोत्साहित करने और सेवा मानकों के स्तर को उन्नत करने के लिए, रजिस्ट्रीकरण की आवश्यकता है। प्रशिक्षण संस्थानों से सुविधाओं के न्यूनतम स्तर को बनाए रखने और पर्यटन उद्योग और प्रशिक्षार्थियों के सम्पूर्ण हित के लिए प्रशिक्षण प्रत्याशित है।

हिमाचल में साहसिक खेल-कूद, मुख्य पर्यटक आकर्षण के रूप में उभर रहा है किन्तु विभिन्न साहसिक खेल-कूद में सुरक्षा स्तरों के परिवर्तन के लिए किसी विधि के अधीन कोई भी उपबन्ध नहीं है। साहसिक खेल-कूद क्रियाकलापों में पर्यटकों के मन में विश्वास पैदा करने के लिए, साहसिक खेल-कूद में सुरक्षा के स्तरों को बनाने तथा प्रवर्तित करने के लिए एक वैध विरचना का होना आवश्यक है। इसलिए, पर्यटन प्रयोजनों और सुरक्षा स्तरों की व्यवस्था करने के लिए साहसिक खेल-कूद इकाईयों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण आवश्यक है। हिमाचल प्रदेश पर्यटन व्यवसाय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1988 की विद्यमान विधायी विरचना इन सब परिवर्तनों को एकरूपता नहीं दे सकती, इसलिए विधान को स्वअन्तर्विष्ट बनाने के लिए पुराने अधिनियम के स्थान पर नया अधिनियम लाना प्रस्तावित है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

शिमला
तारीख 2002.

प्रो० प्रेम कुमार धूमल,
मुख्य मन्त्री।

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 9, राज्य सरकार द्वारा पर्यटन विकास बोर्ड को दिए जाने वाले अनुदान का उपबन्ध करता है। सरकार को, राजकोष से, बोर्ड के कृत्यों को दक्षतापूर्ण पूरा करने के लिए सहायता अनुदान के रूप में लगभग चौदह लाख रुपये प्रतिवर्ष अनावर्ती व्यय की व्यवस्था करनी होगी।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 64, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने को राज्य सरकार को सशक्त करता है। यह प्रस्तावित प्रत्यायोजन आवश्यक और सामान्य स्वरूप का है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

[पर्यटन विभाग नस्ति संख्या टी0 एस0 एम0-5-3/86-जिल्द-2]

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2002 की विषय-वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन, उपर्युक्त विधेयक को बिगान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं।

Bill No. 3 of 2002.

**THE HIMACHAL PRADESH TOURISM DEVELOPMENT AND
REGISTRATION BILL, 2002**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to re-enact a law relating to registration of persons engaged in tourist trade, constitution of the Tourism Development Board and other matters connected therewith.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-third Year of the Republic of India, as follows:—

CHAPTER-I

PRELIMINARY

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Tourism Development and Registration Act, 2002.

Short title,
extent and
commence-
ment.

(2) It extends to the whole of the State of Himachal Pradesh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. (1) The Government may direct that all or any of the provisions of this Act shall not, subject to such terms and conditions as it may specify, apply generally,—

Exemptions.

- (i) to a premises used for a public purpose of a charitable nature or to any class of premises used for such purposes;
- (ii) to a premises held by a public trust for a religious or charitable purpose and let out at a nominal rent;
- (iii) to a premises held by a public trust for a religious or charitable purpose and administered by a local authority; and
- (iv) to a rest house, dak bungalow, circuit house, inspection hut, serai or any institution or premises managed or run by the Government or a local authority.

(2) The Government may also by order, direct that all or any of the provisions of Chapter-IV shall not apply to such hotels or institutions, or such class of hotels or institutions, subject to such terms and conditions, if any, as may be specified in the order.

3. In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context,—

Definitions.

- (a) “adventure sports” means an outdoor activity undertaken for sports or recreation on land or in water or in the air, as the case may be, which shall include water sports, aero-sports, trekking, rafting, skiing, heli-skiing, bunji-jumping and

ballooning with an inherent risk to the life or limb of the participant or any other sports as may be notified by the Government from time to time;

- (b) "adventure sports operator" means any person or organization or enterprise, as the case may be, engaged in or offering to engage for adventure sports on commercial basis i. e. for the purpose of training, recreation or sports;
- (c) "Board" means Tourism Development Board established under section 4 of this Act;
- (d) "Certificate of registration" means a certificate issued under this Act;
- (e) "Council" means Tourism Development Council established under section 17 of this Act;
- (f) "Government" means the Government of Himachal Pradesh;
- (g) "guide" means a person who engages himself as a paid guide for the tourists;
- (h) "local authority" means the Municipal Corporation or Municipal Council or Cantonment Board or Nagar Panchayat or Gram Panchayat or Special Area Development Authority;
- (i) "malpractice" includes cheating, touting, impersonation, obstruction in allowing free choice for stay or travel arrangement, charging rent or remuneration higher than that fixed under this Act, failure to display the rent list, failure to give cash memos, wilful failure to execute an order within the stipulated period and according to the terms agreed upon, failure to provide accommodation to the tourists when available, failure to provide promised facilities and providing substandard equipment and untrained personnel by the adventure sports operator:

Explanation.—The expression "touting" means coercing for accommodation, transportation, sight seeing or pestering for any particular premises, establishment or any other services connected with tourism with the consideration of personal benefit;

- (j) "Official Gazette" means the Rajpatra, Himachal Pradesh;
- (k) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;
- (l) "prescribed authority" means the authority notified as such by the Government; provided that different authorities may be notified for different areas and for different provisions of this Act;

- (m) "season" means the period from 15th April to 15th July and from 15th September to 15th January; and rest of the period shall constitute "off-season";
- (n) "tourism unit" means any establishment providing facilities and services to the tourists and includes hotel, resorts, motels, time share units, apartments, house-boats, motor caravans, guest houses, yatri niwases, restaurants and bars, amusement parks, theme parks, water sports centres, aerospots centres, golf courses, handicraft village complexes, camps, river cruises, lake cruise projects, light and sound shows, adventure sports complexes, training institutes for adventure sports or tourism industry doing business for a monetary consideration and any other type of establishment as may be notified by the Government from time to time;
- (o) "tourism unit operator" means any person who owns, runs or operates a tourism unit and includes a person managing or operating the affairs on behalf of the proprietor;
- (p) "tourist" means a person or group of persons, including pilgrims visiting the State of Himachal Pradesh; and
- (q) "travel agent" means a person engaged in the business of making travel arrangements for tourists for monetary consideration:

Explanation.—the expression "travel arrangements" includes,—

- (a) arrangement for transportation by any mode ;
- (b) arrangement for lodging with or without board; and
- (c) rendering other services such as arranging for games and sports or receipt or despatch of personal belongings of a tourist or taking photograph(s) of a tourist, hiring of guides, photographers, arranging equipment for travel or adventure sports.

CHAPTER-II

TOURISM DEVELOPMENT BOARD

4. (1) The Government may, by notification in the Official Gazette, establish a Board to be known as the 'Tourism Development Board' for carrying out the purposes of this Act.

Establishment and constitution of the Board.

(2) The Board shall be a body corporate by the name aforesaid, having perpetual succession and a common seal, with power to acquire, hold and dispose of property and to contract and may, by the said name sue and be sued.

(3) The Board shall consist of the following members:—

(i) OFFICIAL MEMBERS :

(a) Chief Minister of Himachal Pradesh *Chairman*

- (d) the Member-Secretary of the Board shall make available the notice alongwith the agenda of the meeting to all the members of the Board atleast twenty four hours before the meeting takes place; and
 - (e) the presence of 50% members of the total number of the members of the Board shall form the quorum of a meeting.
- (2) The decisions of the Board shall be attested and maintained by the Member-Secretary of the Board.

Powers and
functions
of the
Board.

8. (1) The Board may,—

- (a) advise the Government to lay down policy guidelines for the development and promotion of tourism industry in the State;
- (b) publicise Himachal as an attractive tourist destination within and outside the country and establish image of Himachal Pradesh as a safe reliable tourist destination;
- (c) undertake improvement in the tourist areas to the extent possible within the resources of the Board;
- (d) undertake income generating projects for the benefit of tourism industry/tourists in general;
- (e) provide assistance to the Department of Tourism, Tourism Development Councils, Tourism Development Corporation, other departments of the Government, Semi Government Organizations, Non-Government Organizations to promote tourism industry and to enter into joint ventures with such departments and agencies;
- (f) undertake human resource development effort for the development of sustainable tourism industry in the State ;
- (g) work in collaboration with counterpart bodies in other States for the overall development of tourism industry and to undertake joint projects with other Government and Semi-Government Organisations elsewhere in the country ;
- (h) create employment opportunities and to earn foreign exchange through development, expansion and promotion of tourism and civil aviation ;
- (i) carry out action research or get it done as per necessity to find out ways to eliminate problems encountered in tourism sector so as to provide quality services to the tourists ;
- (j) take steps to motivate the private sector to encourage the tourists to visit the places of religious and cultural

importance, high mountains and the areas of alluring natural beauty of the State by making use of the existing physical infrastructure related with tourism in an organised and effective manner ;

- (k) take steps to organize constructive and tourism promotional activities including international seminars and conferences, trade fairs, cultural youth festivals and sports competitions and to encourage private sector to organize and participate in such activities ;
- (l) give priority to rural tourist destinations while developing new tourist destinations and consolidating tourism infrastructure and facilities and to motivate local rural community to undertake various activities for rural tourism development ;
- (m) mobilize or get mobilized investment for infrastructure building and development of new tourist destinations ;
- (n) protect and promote religious places of tourist interest, to extend facilities and services in such places of religious and cultural importance for attracting more tourists and for developing religious tourism ;
- (o) develop and promote wildlife and eco-tourism ;
- (p) implement or get implemented publicity programmes on various levels for raising tourism consciousness ;
- (q) make special arrangements for the security of the tourists by standardizing services and facilities provided to the tourists by tourism entrepreneurs ;
- (r) provide and make provisions for necessary services and consultation in subjects related to tourism ;
- (s) negotiate with foreign or international organizations with the approval of Government for the fulfilment of the Board's objectives ;
- (t) approve necessary budget for conducting Board's annual programmes ;
- (u) perform other necessary activities related with the development, extension and promotion of tourism ;
- (v) issue guidelines to the Tourism Development Councils ;
- (w) to assist in the formation and functioning of society related to adventure tourism ; and
- (x) perform such other functions as may be entrusted to it by the Government from time to time.

(2) The Board may, with the approval of the Government, charge fee or rent,—

- (a) for the registration and renewal of registration of tourism units, travel agents, guides, adventure sports operators or other persons requiring registration and licence under this Act ; and
- (b) for promotion of destination or location by way of common publicity.

(3) The Board may, on its own, charge fee of rent,—

- (a) for the parking of vehicles provided by the Board to the tourists ; and
- (b) for the facilities provided by the Board to the tourists in tourism units.

(4) The Board may, receive donations and grants from any Government, Semi-Government or Non-Government Organizations.

Grants to
the Board
by the
Govern-
ment.

9. The Government may, after due appropriation made by a Legislature by law, in this behalf pay to the Board, on such terms and conditions as the Government may determine by way of loans or grants such sums of money as the Government may consider necessary for the efficient discharge by the Board of its functions under this Act.

Funds of
the Board.

10. (1) The Board shall have its own funds and all receipts of the Board shall be credited thereto and all payments of the Board shall be made therefrom.

(2) The Board shall have power, subject to the provisions of this Act, to spend such sums as it thinks fit to cover all administrative expenses of the Board and on objects or for purposes authorised by this Act and such sums shall be treated as expenditure out of the funds of the Board.

(3) All moneys standing at the credit of the Board which can not immediately be applied as provided in sub-section (2) shall be deposited in the State Bank of India or in such Scheduled Bank or Co-operative Bank in the State or Post Office and subject to such conditions as may from time to time be specified by the Government:

Explanation.—In this sub-section, the expression “Scheduled Bank” has the same meaning as assigned to it in clause (e) of section 2 of the Reserve Bank of India Act, 1934.

2 of 193

Investment
of funds.

11. (1) The Board may invest its funds in the securities of the Government or in such other manner as may be prescribed.

Borrowing
power of
the Board.

12. (1) The Board may, with the approval of the Government or in accordance with the terms of any general or special authority given to it by the Government, borrow money from any source by issuing the bonds, debentures or such other instruments as it may deem fit for discharging all or any of its functions under this Act.

(2) The Government may guarantee, in such manner as it thinks fit, the repayment of the principal and the payment of interest thereon with respect to the loans borrowed by the Board under sub-section (1).

(3) Subject to such limits as the Government may, from time to time, lay down, the Board may borrow temporarily by way of overdraft or otherwise such amount as it may require for discharging its functions under this Act.

13. (1) The Government may depute to the service of the Board such of its employees from the Tourism Department or from any other Department as it consider necessary.

Employees
of Board.

(2) The service conditions of deputed employees shall be such as may be prescribed by the Government from time to time.

(3) The Board may employ any person on contract basis as it may consider necessary on such terms and conditions as may be determined by it.

14. (1) The Board shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts including the profit and loss account and the balance-sheet in such form as may be prescribed by the Government.

Accounts
and Audit.

(2) The accounts of the Board shall be audited annually by the Local Audit Department, Himachal Pradesh and any expenditure incurred by it in connection with such audit shall be payable by the Board to the Local Audit Department, Himachal Pradesh.

(3) The Local Audit Department, Himachal Pradesh shall have the same rights and privileges and authority in connection with such audit as Accountant General of Himachal Pradesh has in connection with the audit of Government accounts and in particular, shall have the right to demand the production of books, accounts, connected vouchers, documents and papers of the Board.

(4) The accounts of the Board as certified by the Local Audit Department, Himachal Pradesh together with the audit report thereon shall be forwarded annually to the Government and the Government shall cause the same to be laid before the Legislative Assembly.

15. (1) Notwithstanding anything contained in section 14, the Government may order a special audit of the accounts of the Board to be conducted by such person or agency as it may think fit, relating to any particular transaction or a class or series of transactions for a particular period.

Special
audit of
accounts.

(2) Where an order is made under sub-section (1), the Board shall present or cause to be presented for audit such accounts and shall furnish to the person or agency appointed under sub-section (1), such information as the said person or agency may require for the purpose of audit.

Annual
report.

16. The Member-Secretary of the Board shall prepare the annual report of the activities of the Board within three months from the date of the expiry of the financial year and a copy thereof shall be forwarded to the Government.

CHAPTER-III

TOURISM DEVELOPMENT COUNCIL

Establish-
ment and
constitution
of the
Council.

17. (1) The Government may, by notification in the Official Gazette, establish a Council to be known as the "Tourism Development Council" for carrying out the purposes of this Act for a specific tourist place, as may be notified by the State Government.

(2) The Council shall be a body corporate by the name aforesaid, having perpetual succession and a common seal, with power to acquire, hold and dispose of property and to contract and may, by the said name sue and be sued.

(3) The Council shall consist of the following members, namely:—

(i) Official Members :

- | | |
|--|-----------------------|
| (a) Deputy Commissioner | <i>Chairman.</i> |
| (b) Additional Deputy Commissioner and in his absence, the concerned Sub-Divisional Officer (Civil) | <i>Vice-Chairman.</i> |
| (c) Divisional Forest Officer | <i>Member.</i> |
| (d) Executive Engineer (P.W.D.) | <i>Member.</i> |
| (e) Executive Engineer (I.P.H.) | <i>Member.</i> |
| (f) Executive Officer or Secretary of the Municipal Council or Nagar Panchayat or Gram Panchayat, as the case may be | <i>Member(s).</i> |
| (g) Town Planner | <i>Member.</i> |

(ii) Non-Official Members :

- | | |
|---|---------------------|
| (a) Representatives of Hotel Associations | <i>Two Members.</i> |
| (b) Representative of Travel Agent Associations | <i>One Member.</i> |
| (c) Representatives from other interested groups of tourism industry | <i>Two Members.</i> |
| (d) Four non-official members, to be nominated by the Government, by notification, from amongst the persons, who have | |

outstanding contribution or expertise in the field of development and promotion of tourism industry and having experience of working in the tourism and travel trade for atleast 10 years.

- (iii) District Tourism Development Officer or Assistant Tourism Development Officer to be nominated by the Government .. *Ex-Officio Member-Secretary.*

(4) The non-official members shall be paid such allowances as may be notified by the Government from time to time.

18. (1) The non-official members shall hold office of the Council for a period of two years from the date of their appointment and they shall be eligible for re-appointment.

Term of office.

(2) If the Government considers that the continuance in office of any non-official member is not in the interest of the Council, the Government may make an order terminating his term and thereupon, he shall cease to be a member of the Council notwithstanding the fact that the term to which he was nominated has not expired.

(3) Any non-official member of the Council may resign his office by a letter addressed to the Chairman and the resignation shall take effect from the date of acceptance of his resignation by the Chairman.

19. A person shall be disqualified for being a member if he—

Disqualifications.

- (a) has been convicted and sentenced to imprisonment for an offence, which in the opinion of the Government involves moral turpitude; or
- (b) is an un-discharged insolvent ; or
- (c) is of unsound mind; or
- (d) has been dismissed or removed from the service of the Government or a Corporation owned or controlled by the Government; or
- (e) has directly or indirectly by himself or by any partner, employer or employee, any share or interest in any contract or employment with, by or on behalf of the Council.

20. (1) An ordinary meeting of the Council shall be held once in a quarter, on the date, time and place fixed by the Chairman.

Meetings of the Council.

(2) The Chairman may, whenever he thinks fit, call a special meeting.

(3) Every meeting of the Council shall be presided over by the Chairman and in his absence by the Vice-Chairman and in the absence of both, by any other member chosen by the members present.

(4) The Member-Secretary of the Council shall make available the notice alongwith the agenda of the meeting to all the members of the Council atleast twenty four hours before the meeting.

(5) The presence of 50% -members of the total number of the members of the Council shall form the quorum of a meeting.

(6) The proceedings of the meeting of the Council shall be attested by the Chairman and maintained by the Member-Secretary of the Council.

(7) The Council may from sub-committees as may be considered necessary to perform its functions and activities.

(8) The duties, functions and the term of office of the sub-committees formed under sub-section (7) shall be determined by the Council.

Powers
and functions of the
Council.

21. (1) The Council shall systematically execute and get executed necessary programmes and manage all the activities of the Board for achieving the objectives of this Act.

(2) The Council may,—

- (a) provide and maintain the tourism related services such as information, reservations, guidance, parking, toilets, cleanliness of tourist spots, environmental upgradation, publicity etc;
- (b) assist the local body in maintaining the sanitation and infrastructural facilities at the tourist spots;
- (c) build and maintain parks, lakes and recreation centres, fountains or any other such facility, which may enhance the tourism value of the area;
- (d) take up developmental measures for various sections of tourism industry and those engaged in allied activities;
- (e) regulate the construction, expansion, maintenance and operation of all tourism units and allied activities, subject to the general superintendence and control of the Board, in such a manner so that the tourism activities become environmentally and culturally sustainable;
- (f) prepare a tourism master plan for its area and all tourism units and establishments performing tourism related activities shall conform to the said master plan and the Council may order to modify or close down the tourism units or establishments not conforming to the master plan; and
- (g) perform such other duties and functions as may be entrusted to it from time to time by the Board or the Government.

(3) The Council may,—

- (i) charge fee on any of the direct services provided by it; and

- (ii) receive donations or grants from the Board, the Central Government, the State Government, Semi-Government and Non-Government Organizations and any other source.

22. (1) The Council shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts including the profit and loss account and the balance-sheet in such form as may be prescribed by the Government.

Accounts and audit.

(2) The accounts of the Council shall be audited annually by the Local Audit Department, Himachal Pradesh and any expenditure incurred by it in connection with such audit shall be payable by the Council to the Local Audit Department, Himachal Pradesh and the Council shall forward the same to the Board.

(3) The Local Audit Department, Himachal Pradesh shall have the same rights, privileges and authority in connection with such audit as Accountant General of Himachal Pradesh has in connection with the audit of Government accounts and in particular, shall have the right to demand the production of books, accounts, connected vouchers, documents and papers of the Council.

(4) The accounts of the Council as certified by the Local Audit Department, Himachal Pradesh together with the audit report thereon shall be forwarded annually by the Council to the Board.

23. (1) Notwithstanding anything contained in section 22, the Government may order a special audit of the accounts of the Council to be conducted by such person or agency as it may think fit relating to any particular transaction or a class or series of transactions for a particular period.

Special audit of accounts.

(2) Where an order is made under sub-section (1), the Council shall present or cause to be presented for audit such accounts and shall furnish to the person or agency appointed under sub-section (1), such information as the said person or agency may require for the purpose of audit.

24. The Member-Secretary of the Council shall prepare the annual report of the activities of the Council within three months from the date of the expiry of the financial year and a copy thereof shall be forwarded to the Board as well as to the Government.

Annual report.

CHAPTER-IV

REGISTRATION OF TOURISM UNITS, TRAVEL AGENTS, GUIDES AND ADVENTURE SPORTS OPERATORS

25. (1) Every person intending to operate a tourism unit shall, before operating the tourism unit, apply for registration to the prescribed authority in the prescribed manner :

Registration of the tourism unit.

Provided that any person already operating a tourism unit on the date of commencement of this Act, shall apply for registration within ninety days from the date of commencement of the Act :

Provided further that any person, operating a tourism unit, makes any addition or alteration in the tourism unit, shall apply for fresh registration within ninety days from the date of such addition or alteration.

(2) Every application made under sub-section (1) shall be disposed of within a period of sixty days from the date of receipt of application, failing which the application shall be deemed to have been accepted for registration.

(3) No person shall operate a tourism unit unless it is registered in accordance with the provision of this Act.

Registrat-
ion of the
travel agent
or guide.

26. (1) No person shall carry on the business of a travel agent or a guide unless he is registered in accordance with the provisions of this Act :

Provided that no person shall be eligible to be registered as a guide, unless he possesses such qualifications as may be prescribed :

Provided further that notwithstanding any prescribed qualification, the persons who are working as guides, on the date of commencement of this Act, shall *ipso-facto* be registered as guides.

(2) Every person intending to act as a travel agent or a guide shall, before he commences to act as such, apply for registration to the prescribed authority in the prescribed manner :

Provided that any person acting as a travel agent or a guide on the date of commencement of this Act, shall apply for registration within ninety days from the date of commencement of this Act.

(3) Every application made under this section shall be disposed of within a period of sixty days from the date of receipt of application, failing which the application shall be deemed to have been accepted for registration.

Registrat-
ion of the
adventure
sports
operator.

27. (1) No person shall carry on the business of adventure sports unless he is registered in accordance with the provisions of this Act.

(2) Every person intending to operate an adventure sports institute or to act as an adventure sports operator shall, before he commences to act as such, apply for registration to the prescribed authority in the prescribed manner.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (2), any person already acting as an adventure sports operator shall apply for

registration within ninety days from the date of commencement of this Act.

(4) Every application made under this section shall be disposed of within a period of sixty days from the date of receipt of application, failing which the application shall be deemed to have been accepted for registration.

28. The prescribed authority shall, unless registration is refused under sections 25 or 26 or 27, direct the name and particulars of the tourism unit or travel agent or guide or adventure sports operator, as the case may be, cause to be entered in the register maintained for the purpose and shall issue a certificate of registration to the tourism unit or the travel agent or the guide or the adventure sports operator, as the case may be, in the prescribed form.

Certificate of registration of the tourism unit, travel agent, guide and adventure sports operator.

29. The prescribed authority may refuse registration of the tourism unit or travel agent or guide or adventure sports operator, as the case may be, under this Act on any of the following grounds:—

Refusal to register the tourism unit, travel agent, guide and adventure sports operator.

- (a) if the tourism unit operator or the travel agent or the guide or the adventure sports operator, as the case may be, is convicted of any offence under Chapters-XIV and XVI of the Indian Penal Code, 1860 or under any of the provisions of this Act or any offence punishable under any law providing for prevention of hoarding, smuggling or profiteering or adulteration of food or drugs or corruption and two years have not elapsed since the termination of the sentence imposed upon him;
- (b) if the tourism unit operator or the travel agent or the guide or the adventure sports operator, as the case may be, has been declared an insolvent by a court of competent jurisdiction and has not been discharged;
- (c) if the name of tourism unit operator or a travel agent or a guide or an adventure sports operator, as the case may be, has been removed from the register on the grounds mentioned in clauses (c), (d), (e) or (g) of section 30 and three months have not elapsed since the date of such removal;
- (d) if the premises of the tourism unit do not conform to the prescribed standard;
- (e) if the travel agent or a guide or an adventure sports operator does not possess any of the prescribed qualifications;
- (f) if the tourism unit operator or the travel agent or the guide or the adventure sports operator, as the case may be, does not hold a certificate of registration required to be held by him under this Act;
- (g) if the tourism unit operator fails to produce the proof that the structure of the tourism unit has been built in accordance with the building bye-laws made under the provisions of the

Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 or under any other local laws in force; and

12 of 1977

- (h) if in the opinion of the prescribed authority, there is any sufficient ground to be recorded in writing, for refusing registration:

Provided that no application for registration shall be refused unless the person applying for registration has been allowed an opportunity of being heard.

Removal
of name
of tourism unit,
travel agent,
guide and
adventure
sports operator
from the
register.

30. The prescribed authority may, by order, in writing, remove the name of tourism unit or travel agent or guide or adventure sports operator, as the case may be, from the register and cancel the certificate of registration issued under section 28, on any of the following grounds, namely:—

- (a) if the tourism unit operator or the travel agent or the guide or the adventure sports operator, as the case may be, ceases to operate the tourism unit or ceases to act as a travel agent or a guide or an adventure sports operator for which he is registered;
- (b) if the tourism unit operator or the travel agent or the guide or the adventure sports operator, as the case may be, is convicted of any offence under Chapters-XIV and XVI of the Indian Penal Code, 1860 or under any of the provisions of this Act or of any offence punishable under any law providing for the prevention of hoarding, smuggling or profiteering or adulteration of food or drugs or corruption and two years have not elapsed since the termination of the sentence imposed upon him;
- (c) if the tourism unit operator or the travel agent or the guide or an adventure sports operator, as the case may be, is declared insolvent by a court of competent jurisdiction and has not been discharged;
- (d) if the tourism unit operator or the travel agent or the guide or the adventure sports operator, as the case may be, fails to comply with any of the provision of this Act or rules framed thereunder;
- (e) if the tourism unit operator fails to remove a lodger or wilfully keeps the lodger in a tourism unit, who becomes a nuisance for the inmates in his tourism unit as well as adjoining building(s);
- (f) if any complaint of malpractice is received and proved against the tourism unit operator or the travel agent or the guide or adventure sports operator, as the case may be;
- (g) if the tourism unit operator makes structural changes in the tourism unit without the approval of the Development Authority constituted under the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 or any other local authority constituted under the local laws;

45 of 1860

19 of 1977

- (h) if the tourism unit operator or the travel agent or the guide or the adventure sports operator, as the case may be, has obtained the certificate of registration by misrepresentation or fraud ;
- (i) if the adventure sports operator does not maintain equipments, manpower and other facilities according to prescribed standards for safety; and
- (j) if the adventure sports operator does not take the precautions regarding safety measures, as may be prescribed :

Provided that before removing the name of any tourism unit or the travel agent or the guide or the adventure sports operator, as the case may be, from the register under this section, the prescribed authority shall give a notice to the tourism unit or the travel agent or the guide or the adventure sports operator, as the case may be, indicating the grounds on which it is proposed to take action after giving him an opportunity of being heard.

31. The prescribed authority may in consultation with the committee to be constituted in the prescribed manner,—

Classification of tourism unit.

- (a) classify the tourism units into various classes, as may be prescribed; and
- (b) fix the number of lodgers to be accommodated in each room in case of accommodation.

32. (1) The prescribed authority shall, notify the fair rates or service charges, if any, commensurate to the standard/class of the tourism units and quality of food, accommodation and service, as specified by the tourism unit, which may be charged during "season" and "off-season" periods for boarding or lodging or for both from the tourists :

Notifying the fair rates.

Provided that in case of dispute with regard to the rates to be charged, the decision of the committee constituted under section 31, shall be final :

Provided further that the rates for lodging shall be notified with reference to each room or specified accommodation and the number of the lodgers to be accommodated.

(2) The prescribed authority shall notify the fair rates, as may be specified by the travel agent or by the guide, which may be charged for the services rendered to a person engaging him as such.

(3) The prescribed authority shall, notify the fair rates, as may be specified by the adventure sports operator commensurate to the standard of the adventure sports and other facilities, which may be charged by him from the tourists or from the customers.

33. The prescribed authority shall, from time to time, revise the fair rates notified under section 32.

Revision of fair rates.

Notifying the fair rates until notified by the prescribed authority.

34. Till such time, the prescribed authority does not notify the fair rates and the number of lodgers to be accommodated in each room, as required under sections 31 and 32, the tourism unit operator or the travel agent or the guide or the adventure sports operator, as the case may be, shall notify the fair rates and intimate the same to the prescribed authority by 31st day of July each year and separate rates may be fixed for "season" and "off-season" periods and such rates shall be effective from 1st October of that year till 30th September of the following year.

Display of information.

35. Where under sections 32 and 33 the prescribed authority has notified or revised the fair rates, the number of lodgers to be accommodated in each room, or even in case where the prescribed authority has not notified the fair rates, the tourism unit operator or the travel agent or the guide or the adventure sports operator, as the case may be, shall display a notice of the fair rates, the number of lodgers to be accommodated in each room at a conspicuous place in a tourism unit, business premises of the travel agent, the guide or the adventure sports operator and an agent of the tourism unit operator shall also keep a copy certified by the prescribed authority, of such information on his person.

Charges recoverable in excess of fair rates.

36. (1) Notwithstanding any agreement to the contrary, no tourism unit operator or travel agent or guide or adventure sports operator, as the case may be, shall charge any amount in excess of the fair rates notified.

(2) Any sum paid by the lodger or by a customer in excess of the fair rates fixed shall be refundable to the lodger or to a customer by the tourism unit operator or the travel agent or the guide or the adventure sports operator, as the case may be, through the prescribed authority.

No ejectment to be made if fair rates paid.

37. No tourism unit operator or travel agent or guide or adventure sports operator, as the case may be, shall evict or refuse any service to a lodger or to a customer so long as he pays or is ready and willing to pay the fair rates notified and observes and implements the other conditions of his agreement in so far as they are consistent with the provisions of this Act.

When tourism unit operator may recover possession.

38. (1) Notwithstanding anything contained in this Act a tourism unit operator shall be entitled to recover possession of the accommodation provided by him on obtaining an order from the prescribed authority to the effect that :—

- (a) the lodger has been guilty of a conduct which constitutes a nuisance or annoyance to any other lodger ; or
- (b) the lodger has failed to pay the accommodation charges ; or
- (c) the lodger has failed to vacate the accommodation on termination of the period of the agreement in respect thereof :

Provided that before issuing an order under this section, the prescribed authority may conduct a summary enquiry and shall pass an appropriate order in a summary manner :

Provided further that any party aggrieved by an order of the prescribed authority may prefer an appeal before the District Magistrate of the concerned district who shall dispose it of in a summary manner.

(2) If the lodger against whom the order has been passed under sub-section (1) does not comply with the said order, the prescribed authority may take assistance from the police for the implementation of the order and every police officer shall render the assistance for the implementation of the said order.

39. Every tourism unit operator or travel agent or guide or adventure sports operator, as the case may be, shall present detailed bills to the lodgers and other customers and shall give receipt in acknowledgement of all payments.

Tourism unit operator, travel agent, guide and adventure sports operator to Present detailed bills.

40. If a tourism unit operator confirms a booking, at a particular rate, he shall, even if accommodation at higher rates alone is available at the time of arrival of the person for whom accommodation stands booked, be honoured at the booked rate.

When the tourism unit operator may honour confirmation of bookings at a particular rate.

41. (1) The prescribed authority or any officer authorised by the Government may, in order to ensure that any of the provisions of this Act is not being implemented by the tourism unit operator or travel agent or guide or adventure sports operator, as the case may be, enter the tourism unit or business premises of the travel agent or guide or adventure sports operator and inspect all accounts, registers, documents and other books with or without prior notice.

Power of entry, inspection, seizure and supply of statistical data by tourism unit operation etc.

(2) If the prescribed authority or any officer authorized by the Government has reasons to suspect that any tourism unit operator or travel agent or guide or adventure sports operator, as the case may be, is attempting to evade or has evaded any of the provisions of this Act, such authority or officer may, for reasons to be recorded, seize such accounts, registers, documents or other books of such operator or travel agent or guide or adventure sports operator, as the case may be, as may be necessary, and shall grant a receipt of the same and retain the same so long as may be necessary for examination thereof or for the purpose of any proceedings under this Act.

(3) Every tourism unit operator or travel agent or guide or adventure sports operator shall supply statistical data regarding inflow

of tourists and the employees employed by the unit concerned by the tenth of each following month to the prescribed authority.

Travel agent, guide and adventure sports operator not to demand tips etc.

42. The travel agent or guide or adventure sports operator, as the case may be, shall not demand tips, gratuity, presents or commission other than the rates as fixed under section 32 from any person engaging him or from any tourism unit operator in whose tourism unit such person resides or intends to reside.

Insurance.

43. The adventure sports operator shall provide insurance cover as may be prescribed to persons availing of his services.

CHAPTER-V APPEAL AND REVISION

Appeal.

44. (1) Subject to the provisions of sub-section (2), an appeal shall lie from every order of the prescribed authority under this Act to the appellate authority to be appointed by the Government.

(2) Every such appeal shall be preferred within ninety days from the date of communication of the order :

Provided that the appellate authority may entertain the appeal after the expiry of the said period of ninety days if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from preferring the appeal in time.

(3) The appellant shall have a right to be represented by a counsel or by a duly authorised agent and the prescribed authority may be represented by such officer or person as the prescribed authority may appoint.

(4) On receipt of any appeal, the appellate authority shall, after giving the appellant a reasonable opportunity of being heard and after making such inquiry as it deems proper, pass such order as it may deem fit, after recording the reasons thereof.

Revision.

45. The revisional authority, to be appointed by the Government, may, either on its own motion or on an application made by an aggrieved party, call for the records of any case disposed of by an appellate authority, for the purpose of satisfying itself as to the correctness, legality or propriety of any order passed by appellate authority and may pass such order thereon as it may deem fit and such order shall be final :

Provided that no such application for revision shall be entertained after the expiry of three months from the date of communication of the order passed by the appellate authority :

Provided further that revisional authority on its own motion can call for the record of any case decided or pending before any authority and pass such order as it may deem fit :

Provided further that no order under this section shall be made to the prejudice of a person unless he has had a reasonable opportunity of being heard either personally or through a counsel or by a duly authorised agent.

CHAPTER-VI

OFFENCES AND PENALTIES

46. Any person carrying on the business of a tourism unit or travel agent or guide or adventure sport or any other business connected with tourist trade, as the case may be, without a proper registration under this Act or in contravention of any of the provisions of this Act, shall be punishable with imprisonment for a term not exceeding six months or with fine not exceeding ten thousand rupees or with both, and if the breach is a continuing one with a minimum fine of rupees two hundred per day and maximum of two thousand rupees per day till the default continues.

Penalty for default in registration.

47. If any person who is required to make a statement under this Act, wilfully makes a false statement or suppresses a material fact with the intention to mislead the prescribed authority, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months or with fine not exceeding two thousand rupees or with both.

Penalty for false statement.

48. Any person who lends, transfers or assigns the certificate of registration issued under this Act, without the permission in writing of the prescribed authority, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine not exceeding ten thousand rupees or with both.

Certificate not to be assigned without permission.

49. (1) Any person registered under this Act shall at all times, on demand, produce and show his certificate of registration to any of the following persons, namely :—

Certificate to be shown to persons on demand.

- (a) the prescribed authority or any other officer duly authorised by it in this behalf;
- (b) any authority authorized by the Government or any officer authorized by the Director, Tourism, Himachal Pradesh ; and
- (c) any bonafide customer.

(2) Any person who refuses on demand to show his certificate to, or allowed to be read by, any of the persons authorized to demand it, shall be punishable with fine not exceeding five thousand rupees.

50. Any person who commits a malpractice or contravenes any other provision of this Act for which no specific penalty has been provided, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months or with fine not exceeding ten thousand rupees or with both.

Penalty for malpractice

Obstructing
lawful au-
thorities.

51. If any person wilfully obstructs or offers any resistance to, or otherwise interferes with the discharge of the functions of the prescribed authority or any other officer authorized by it, exercising any power, or performing any duties conferred or imposed upon it or him by or in pursuance of this Act or the rules made thereunder, he shall be liable to punishment with imprisonment which may extend to three months or with fine not exceeding one thousand rupees or with both.

Power of
court to
try cases
summarily.

52. All offences under this Act shall be tried in a summary way by a Chief Judicial Magistrate or by any other Judicial Magistrate of the First Class specially authorized by the High Court and the provisions of sections 262 to 265 (both inclusive) of the Code of Criminal Procedure, 1973 shall, as far as may be, apply to such a trial :

2 of 1974

Provided that when at the commencement of or in the course of a summary trial under this section, it appears to the Magistrate that the nature of the case is such that it is for any reason, undesirable to try summarily, the Magistrate shall after hearing the parties record an order to that effect and thereafter recall any witness who may have been examined and proceed to hear or rehear the case in the manner provided by the said Code.

Institution
of proce-
dings.

53. No prosecution shall be instituted against any person for any offence under this Act, except on a complaint made by the prescribed authority or the officer authorized by it or the Government in this behalf.

Powers of
Prescribed
authority
to summon
and enforce
attendance
of witnes-
ses and
other per-
sons.

54. The prescribed authority shall have all the powers of a Civil Court under the Code of Civil Procedure, 1908, while hearing an application under this Act in respect of the following matters, namely:—

5 of 1908

- (a) summoning and enforcing attendance of the complainant or the person against whom complaint is made under this Act and witness required in connection therewith;
- (b) compelling the production of any document; and
- (c) examining witnesses on oath, and may summon and examine *suo motu* any person whose evidence appears to be material.

Composi-
tion of
offences.

55. (1) The prescribed authority may accept from any person who is reasonably suspected of having committed an offence under this Act, a sum of money by way of composition of such offence and may out of the money so received, compensate the person against whom the offence has been committed to the extent the prescribed authority deems reasonable.

(2) On the composition of offence, no further proceedings in respect thereof shall be taken against the accused and if any proceeding has already been instituted against him in a court, the composition shall have the effect of acquittal.

CHAPTER-VII

MISCELLANEOUS

56. (1) Whenever a tourism unit for which a certificate of registration is held by a person devolves by inheritance or otherwise upon any other person or undergoes a change in respect of any particular entered in the register under this Act, such person shall, within thirty days of the date of such devolution or change, notify in writing the fact to the prescribed authority.

Notifica-
tion of
changes.

(2) The prescribed authority shall make necessary changes in the register maintained for the purpose and in the certificate of registration.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (2), the prescribed authority may remove from the register the name of the person in whose favour the certificate was issued and cancel the certificate of registration, if the successor is not eligible to be registered under this Act.

57. When a certificate of registration is cancelled under this Act, the person holding the certificate shall, within seven days from the date of service in the manner prescribed of the order of cancellation, return it to the prescribed authority.

Return of
the certi-
cate of
registration.

58. If a certificate of registration issued under this Act is lost, damaged or destroyed, the prescribed authority shall, on an application made in this behalf by that person holding such certificate and on payment of the prescribed fee, issue a duplicate certificate.

Duplicate
certificate.

59. The tourism unit operator or travel agent or guide or adventure sports operator, as the case may be, registered under this Act shall get renewed the registration certificate after a period of three years from the date of issuance of registration certificate by the prescribed authority and shall also pay renewal licence fee as may be prescribed.

Renewal of
certificate.

60. The certificate of registration shall be kept by a person holding it in a conspicuous place at the principal place of his business and if he has no principal place of business, he shall keep it on his person.

Certificate
of registra-
tion to be
kept ex-
hibited.

61. All proceedings before the prescribed authority under this Act shall be deemed to be judicial proceeding for the purposes of sections 193 and 228 of the Indian Penal Code, 1860.

Proceedings
before the
prescribed
authority
to be judi-
cial proce-
dings.

Indemnity.

62. No suit, prosecution or other legal proceedings, whatsoever shall lie against the Government or any person in respect of anything which is in good faith done or intended to be done under this Act.

Power of Government to apply Act to other persons.

63. The Government may, by notification in the Official Gazette, direct that all or any of the provisions of this Act or of the rules made thereunder shall, with such exceptions, adaptations or modifications as may be considered necessary, apply to persons doing the business in the State of Himāchal Pradesh of outdoor photography or of letting or plying for hire house-boats, dongas, bathing boats, shikaras, dandis, pithus, ponies as may be specified in the notification and the prescribed authority may fix the rates to be charged for the services to be rendered.

Power to make rules.

64. (1) The Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for,—

- (a) the maintenance of registers, books and forms by tourism unit operators, travel agents, guides and adventure sports operators for the conduct of the business;
- (b) the form of application for registration and certificate of registration;
- (c) the fee for the registration, renewal and issuance of duplicate certificate;
- (d) the manner of giving notices under this Act;
- (e) classification of tourism units;
- (f) qualifications for registration as tourism unit operator, travel agent, guide and adventure sports operator;
- (g) safety measures and standards to be adopted in the conduct of adventure sports and facilities to be provided;
- (h) standards for maintenance of hygiene and cleanliness, waste disposal and minimum facilities in various types of tourism units;
- (i) manner of publication of the names and addresses of the tourism unit, travel agent, guide and adventure sports operator removed from the register;
- (j) manner in which the fair rates shall be displayed, type of tickets and receipts to be issued, submission and maintenance of accounts and statement thereof to the prescribed authorities and collection and deposit of licence fee, renewal fee and other dues;

(k) procedure for admission to training institutes, standard of syllabus, staff, equipment and buildings; and

(l) the place where prescribed authority shall hold enquiry under this Act and all matters expressly required to be prescribed under this Act.

(3) All rules made under this section shall be subject to the condition of previous publication.

65. The Himachal Pradesh Registration of Tourist Trade Act, 1988 is hereby repealed :

Repeal and savings.

Provided that anything done or any action taken (including any notification issued, certificate or permission granted or proceedings commenced or continued) under the provisions of the said Act, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Tourism is recognized as an important economic activity. It is a major source of earning to the local population and a foreign exchange earner for the country. Himachal Pradesh has a vast tourism potential on account of environment in the State, because it is culturally and geographically sustainable. Thus it is being perceived as an effective means of bringing propriety to the people of the State in the creation of employment opportunities on a large scale. Tourism requires the participation of local population and private sector to provide the required amenities and services to the tourists. The present Himachal Pradesh Registration of Tourist Trade Act, 1988 lacks a participatory mechanism to promote tourism. Therefore, it is proposed to constitute a Tourism Development Board to seek greater participation of the total population and the private sector in the promotion of tourism and making Himachal Pradesh as an attractive and safe tourism destination. The majority of members of Tourism Development Board are proposed to be drawn from amongst the experts and various interested groups in the tourism industry like hoteliers, travel agents, adventure sports operators, transporters etc. The Board will also be expected to undertake human resource development efforts to create employment opportunities to bring excellence in the services of tourism sector. The Board will also raise resources for providing common services for marketing and facilities and amenities to the tourists. The tourist destinations need special attention for providing amenities to ever increasing number of tourists and to save them from environmental degradation. It is proposed to constitute Tourism Development Councils at various places with majority representation from tourism industry to plan, guide, execute and regulate tourism activities in such a manner that tourism becomes environmentally sustainable and is in harmony with the local culture. These bodies will supplement the efforts of the local bodies in the upgradation and maintaining tourist destinations. They would work under the overall policy framework laid down by the Government and the Tourism Development Board and take up resource generation efforts in their own areas by providing direct and indirect services to the tourists and to the tourism industry. A new chapter is, therefore, proposed to be added to constitute these bodies.

It has also been felt that new types of tourism units other than the hotels and restaurants are coming up or are likely to come up in near future and it is necessary to provide some guidelines for their promotion, standardization of environmental and safety and to make them part and parcel of the tourism promotional efforts of the Board and Councils. There is a need to expand the scope of the Act to include units such as amusement parks, tourism training institutes, house boats, etc. There is a need for registration of such units to encourage internationally accepted norms in their operation and to upgrade the standard of services. The training institutes are expected to maintain a minimum standard of facilities and training for the overall interest of tourism industry and the trainees.

Adventure sports in Himachal Pradesh are coming up as a major tourist attraction but there is no provision under any law for the enforcement of safety standards in various adventure sports. In order to instill the faith of tourists in the adventure sports activities, it is necessary to have a legal frame-work for making and enforcing standards of safety in adventure sports. Thus there is a need to have compulsory registration of adventure sports units for tourism purposes and to provide safety standards. The existing legislative framework of the Himachal Pradesh Registration of Tourist Trade Act, 1988 cannot assimilate all those changes and it is, therefore, proposed to bring a new Act to replace the old Act to make the legislation selfcontained.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

PROF. PREM KUMAR DHUMAL,
Chief Minister.

SHIMLA:
The.....2002.

FINANCIAL MEMORANDUM

Clause 9 of the Bill provides for the grant to be given to the Tourism Development Board by the State Government. The Government may provide rupees Fourteen lakhs per annum approximately as recurring expenditure in the shape of grant-in-aid for the efficient discharge of the functions of the Board out of the State Exchequer.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 64 of the Bill seeks to empower the State Government to make rules for carrying out the purposes of the Act. The proposed delegation of powers is essential and normal in character.

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

[Tourism Department file No. TSM-5-3/86-Vol.-II]

The Governor, Himachal Pradesh, after having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Tourism Development and Registration Bill, 2002, recommends, under article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the said Bill in the Legislative Assembly.

